सम्पादकीय

मजबूत हों स्थानीय निकाय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्थानीय निकायों की राजकोषीय स्थिति पर अध्ययन की शुरुआत करके तथा उसके निष्कर्षों को प्रकाशित करके अच्छी शुरुआत की है। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर पहली ऐसी रिपोर्ट नवंबर 2022 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर एक अध्ययन पेश किया गया। रिजर्व बैंक ने अब 2019-20 से 2023-24 के बजट अनुमानों के आधार पर नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अध्ययन में देश भर के 232 नगर निकायों को शामिल किया गया है। भारत में अक्सर स्थानीय निकायों पर सीमित नीतिगत ध्यान दिया जाता है। आंकिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ कि तुलनात्मक स्वरूप में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक का यह अध्ययन जरूरी नीतिगत ध्यान आकृष्ट करेगा और सार्वजनिक बहस को समृद्ध करेगा। स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना अत्यधिक आवश्यक है। नगर निकायों के संदर्भ में यह बात ध्यान देने लायक है कि भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है और उसे नागरिक क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता है। फिलहाल जो हालात हैं उनके मुताबिक भारत का करीब 60 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) शहरी इलाकों में उत्पन्न हो रहा है और 2050 तक उसकी करीब 50 फीसदी आबादी शहरी इलाकों में रहने लगेगी। बहरहाल अधिकांश नगर निकाय इस बदलाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं, मोटे तौर पर ऐसा इसलिए कि उनके पास संसाधन नहीं हैं।

जैसा कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट दिखाती है, नगर निकायों की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी का केवल 0.6 फीसदी हैं। यह मामूली आंकड़ा भी चुनिंदा नगर निकायों के पक्ष में झुका हुआ है। केवल 10 नगर निकाय कुल राजस्व प्राप्तियों में 60 फीसदी के हिस्सेदार हैं। नगर निकायों का कुल व्यय जिसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय शामिल है, वह 2023-24 के बजट अनुमान में जीडीपी के 1.3 फीसदी के बराबर था। नगर निकायों के राजस्व में संपत्ति कर, कुछ शुल्क और उपयोग शुल्क आदि शामिल होते हैं। संपत्ति कर उसके कुल राजस्व में करीब 60 फीसदी होता है। नगर निकाय केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। राज्य सरकारों, राज्यों के वित्त आयोग के अनुदान तथा अन्य जगहों से आने वाली राशि की बात करें तो 2019-20 और 2022-23 में यह इनकी राजस्व प्राप्तियों में 30 फीसदी की हिस्सेदार रही। केंद्र सरकार का हस्तांतरण उनके राजस्व में 2.5 फीसदी का हिस्सेदार रहा। नगर निकाय बाजार से भी उधारी लेते हैं, हालांकि यह उनके जीडीपी का केवल 0.05 फीसदी है। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने लायक बनाना होगा। अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में सामान्य सरकारी राजस्व और व्यय में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। राजकोषीय शक्तियों में इजाफा तथा सामाजिक जवाबदेही, आर्थिक और सामाजिक परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं के लिए यह हमेशा आसान होता है कि वे अपने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराएं।

भाजपा के नारे "बटेंगे तो कटेंगे' में विरोधियों का हो रहा विरोध और एनडीए का नकारात्मक साथ

सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी और अमित शाह सहित भाजपा के तमाम नेता बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात को हर रैली में दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी का नारा दलित-पिछड़े वर्गों के बीच दरार पैदा करने के लिए और कथित रूप से विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने के लिए कांग्रेस की आलोचना के रूप में अब प्रचारित किया जाने लगा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी का एकमात्र एजेंडा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था वे नहीं चाहते कि एससी, एसटी और ओबीसी आगे बढ़ें और उन्हें उचित पहचान मिले। याद रखें, 'एक हैं तो सेफ हैं'।

अशोक भाटिया

देश के दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव जोर – शोर से हो रहा है। महाराष्ट्र में 20 तारीख को सम्पूर्ण प्रान्त व झारखण्ड में दूसरे चरण की 38 पर व कुछ राज्यों में उपचुनाव की 14 सीटों का चुनाव हो रहा है। इन चुनावों में एक नारा गूंज रहा है 'बटेंगे तो कटेंगे'। इसे दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कट्टर हिंदू की छवि वाले आदित्यनाथ ने। उन्होंने यह नारा तब दिया जह पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। देखते ही देखते यह नारा काफी मशहूर हो गया। इस नारे का इस्तेमाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी हुआ था विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताते हुए इसकी आलोचना की। इस नारे का इस्तेमाल भाजपा के नेता तो कर रहे हैं लेकिन एनडीए में उसके सहयोगी दल इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो इसकी आलोचना कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ इस नारे को देश की एकता से जोड़कर बताते हैं उनका कहना है कि हमारी ताकत एकता है उनका कहना है कि अगर हम बंट गए तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में एक रहना है।वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के समय विपक्ष पर चुप रहने का भी आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष फिलस्तीन पर तो प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेता है, क्योंकि उसे वोट बैंक की चिंता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव इस तरह सेट किया, जिसे भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस का तो समर्थन मिला ही मिला। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इससे हट कर कोई और नारा देने की जगह इसी के इर्द गिर्द अपने नारे और सियासी एजेंडा गढ़ने में जुटी है। इस तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने हिसाब से सियासी एजेंडा सेट करने में लगी हैं। आपको बताते कि बांग्लादेश के संदर्भ में दिया गया यह नारा बटेंगे तो कटेंगे उत्तरप्रदेश की सियासी फिजा में गूंजा और फिर धीर-धीरे जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करने की नैरेटिव में तब्दील होने लगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ योगी के नारे पर अपनी सहमति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहने का संदेश दे कर एक तरह से इसकी तस्दीक ही करते नजर आए हैं। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं को एकजुट रहने की बात करके सीएम योगी के बयान का समर्थन कर दिया था। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मथुरा में साफ कहा था कि हिंदू एकता संघ का जीवन सूत है। हम यह बात आग्रहपूर्वक कहेंगे और आगे इसके लिए प्रयास भी करेंगे। योगी के 'कटेंगे तो बटेंगे' बयान पर संघ का स्पष्ट

कहना है कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हमें अपने को भी बचाए रखना है और दुनिया का भी मंगल करना है। ऐसे में हिंदू एकता जरूरी है। इस बारे में खुद होसबाले ने बताया कि जाति के आधार पर और विचारधारा के आधार पर हिंदुओं की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। भाजपा और संघ इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय राजनीति के असर की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नंबर वन पार्टी थी, लेकिन 2024 में भाजपा को दोनों प्रदेशों में झटका लगा था। इसके चलते भाजपा एक रणनीति के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को पूरी तरह सेट करने में जुटी है ताकि सियासी फिजा को अपने पक्ष में कर सके। सीएम योगी के द्वारा खड़े किए गए बटेंगे तो कटेंगे वाले सियासी नैरेटिव का फिर्केड करने के बजाय विपक्ष उसी आक्रमता के साथ जवाब दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक की आलोचना कर रहे हैं। खड़गे ने महाराष्ट्र में कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम एकजुट हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन असली खतरा किसे है? क्या कोई समस्या है, क्या देश को संघ, भाजपा और मोदी से खतरा है? योगी के 'बटेंगे तो कटेंगे' के नैरेटिव को अखिलेश यादव खुलकर काउंटर करने का दांव चल रहे हैं और उसे जातीय एजेंडे पर सेट कर रहे हैं। अखिलेश हर रोज इस पर अपना बयान दे रहे हैं और बार-बार यही कहते नजर आते हैं दलित-पिछड़े-अल्पसंख्यक जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए एक है और नेक है। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने इस नारे को मुस्लिमों से जोड़ दिया और कहा कि मुसलमानों के घर खुलवीजर से तोड़ने वाले, कैसे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आप सांसद संजय सिंह कहते हैं कि भाजपा को हिन्दुओं की चिंता नहीं, उसे केवल चुनाव जीतने की चिंता है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा कि जाति के आधार पर लोगों को किसने बांटा है? समाज में आज भी मूंछ रखने या शादियों में घोड़ी पर चढ़ने के लिए दलितों पर हमला और उनकी हत्या कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से भाजपा के सहयोगी दलों ने किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र ने कभी भी साम्प्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। यहां के लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबासाहेब अंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन किया है। इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहां के लोगों ने हमेशा साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है। कुछ लोग बाहर से यहां आते हैं और बयान देते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारा नारा सब का साथ और सब का विकास है।

अजित पवार के सुर में सुर मिलाते हुए एकनाथ शिंदे भी नजर आए और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं हो सकती है। जेडीयू ने कहा कि हमारी पार्टी ने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है। भाजपा से हमने बिहार सहित देश के विकास के लिए गठबंधन किया है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। देश एकजुट रहे, आगे बढ़े, इसके लिए हमारी पार्टी ने हमेशा मेहनत की है। जातीय नेता खालिद अनवर का कहना है कि हम लोग ऐसे किसी भी नारे को प्रमोट नहीं कर सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो 'बटेंगे तो कटेंगे' का नारा देकर भाजपा हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था, लेकिन हिंदू वोटों का नहीं।

आज का राशिफल

सभी अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप सभी विशेष लोगों को पूरा सहयोग देंगे। तथा आप एक लक्ष्य बनाने वाले हैं कि आपके जीवन के ऐसे लोगों होंगे है, जहां आपके बिलेरे कुशल लोगों और दुखी लगता, आपको विशेष बातें तो लक्ष्यकाल लाभ पहुंचेगा। लाभ से जिसे हमारे साथ में और लंबित पूरी हो सकेगी। तथा लक्ष्यकाल आपके को लाभकुल होंगे, कठिन परिस्थितियां सकती हैं जी, तथा यह लक्ष्यकालयता हमें लंबा और आपकी में लाभ प्राप्त होगा

मेष
वाणी की शिथिलता के कारण उधार तकरार हो सकती है। सगे-संबंधियों के साथ अनबन होगा। मनोरंजन या घूमने-फिरने के पीछे पैसे खर्च होंगे। शारीरिक, मानसिक व्यग्रता कम करने के लिए आध्यात्मिकता सहायक साबित होगी।

वृष
पठन-लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी। परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से थोड़े निराश हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है।

मिथुन
परोपकार के लिए किए काम आपको आंतरिक खुशी देंगे। आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा। वाणी को सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायक होगी।

कर्क
शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ घर में भी आनंद का वातावरण रहेगा। दोस्तों से लाभ होगा। कार्य सफलता और प्रिय व्यक्ति का साथ आनंदप्रद रहेगा। आर्थिक लाभ और भाग्य वृद्धि की संभावनाएं हैं। नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

सिंह
स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। पिता तथा सरकार से लाभ मिलेगा। आर्थिक योजना अच्छे तरह पूरी कर सकेंगे। व्यापार-धंधे के लिए प्रवास की संभावना है। अन्य लोगों को सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

कन्या
लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से दिन लाभदायक होगा। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा। मित्रों तथा स्वजनों की ओर से उपहार मिलेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

तुला
नौकरी-धंधे या व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ मुलाकात, प्रवास का आयोजन होगा। विचारोत्तेजक युवक-युवतियों के लिए सुनहरे अवसर आएंगे। पुत्र तथा पत्नी से लाभ होगा। घर के बुजुर्गों के जरिए लाभ मिलेगा।

वृश्चिक
मानसिक दुविधा में होने के कारण आप महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे। पानी वाली जगहों तथा अन्य गर्म तरल पदार्थों से सावधान रहें। परिवार या जमीन से संबंधित मामलों पर चर्चा और कहीं जाने की योजना टालें। दुर्घटना से बचें।

धनु
पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख-शांति में दिन व्यतीत होगा। उनका सहयोग मिलेगा। दूरस्थ मित्र और श्रेष्ठीजनों के साथ संपर्क लाभदायक साबित होंगे। अपनी प्रभावशाली वाणी से अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे।

मकर
उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। निर्णायक कार्यों में कम सफलता मिलेगी। आज आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी। मीठी वाणी से आप लाभप्रद, सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित कर सकेंगे। उत्तम भोजन, भेंट उपहारों और वस्त्रों की प्राप्ति होगी।

कुंभ
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थता बनी रहेगी। आनंद की प्राप्ति, जीवनसाथी की निकटता और प्रवास-पर्यटन से आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज के दिन जरा सा भी असंयमित और अनैतिक व्यवहार आपको तकलीफ में डाल सकते हैं।

मीन
श्रेष्ठीजनों एवं मित्रों से उपहार मिल सकता है। उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि बनी रहेगी। सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों के खुश रहने से पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

शख्सियत

श्री राकेश कुमार गढ़वाल (आरएएस)

नमस्कार साथियों हमारे आज की शख्सियत कॉलम के स्तार हैं दमदार व जानदार दबंग शैली के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश कुमार गढ़वाल। इनका जन्म 15 अगस्त सन 1975 को राजस्थान के झुंझुनू जिले हुआ जब पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा था। तभी शायद इनका व्यक्तित्व भी आजाद किस्म का है। मन से आजाद व हमेशा मन मौज में जीने वाले इंसान हैं। नेतृत्व गुण पीओएल एससी बीए कर राजकीय सेवाओं में आए फिलहाल विशिष्ट सहायक राज्यमंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर श्री ओटाराम देवासी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण, जोधपुर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अलवर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़। उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़। उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर श्रीगंगानगर। उपखण्ड अधिकारी, सीकर। उपखण्ड अधिकारी, फोतूपुर सीकर। उपखण्ड अधिकारी, चौहटन बाड़मेर। जिला सहित एचसीएस रीपा, जयपुर में प्रशिक्षण के तहत। एसीईएम खाड़मेर के रूप में प्रशिक्षण में रहे। अलवर एडीएम प्रथम के समय में इनकी कार्यशैली देखने को मिली। मुझे आज भी याद है पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए ये जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की टंकी पर चढ़ाकर ले गए जहां जाकर विभाग के अधिकारियों ने आज तक नहीं देखा। इनकी इस अनूठी व दबंग कार्यशैली का प्रभाव जिले में अनेक गतिविधियों में देखने को मिला है। ये जहां भी रहे अपने दम पर रहे। जनता के हित में व पिड़ित की मदद करने वाले शानदार अधिकारी हैं राकेश कुमार सर। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

16 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- निगवेल हिदाल्गो ने 1810 में स्पेन से मैक्सिको की आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया।
- मैक्सिको की स्वतंत्रता को 1821 में मान्यता मिली।
- विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयिस्की को 1849 में एक भूमिगत संगठन का सदस्य होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी।
- ओकलाहोमा 1870 में अमेरिका का 46वां प्रांत बना।
- अमरीका में फेडरल रिजर्व व्यवस्था का 1914 में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ।
- अल्बर्ट हॉफमैन का आविष्कार लाइसैर्जिक एसिड डाइथलामाइड उर्फ 1938 में आज ही के दिन वजूद में आया।
- अभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था, बात साल 1942 की है, जब कुछ यूरोपीय देशों की सरकारों ने 1945 में ब्रिटेन में एक सम्मेलन आयोजित किया।
- जनरल मोटर्स निगम की 1908 में स्थापना की गई।
- टोक्यो के सईतामा में 1947 में आये चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1,930 लोगों की मौत हो गई।
- वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के बारे में 1965 में पहली सार्वजनिक घोषणा हुई।
- स्काईलैब-4 को 1973 में पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया।
- केप वर्डे, मोजाम्बिक, साओ टोमे और प्रिंसिप 1975 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए।
- पापुआ न्यू गिनी ने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की।
- अमेरिका का पांचवां अंतरिक्ष यान कोलंबिया-5 1982 में एडवर्ड्स सैन्य अड्डे पर उतरा।
- बेनजीर भुट्टो ने 1988 में पाकिस्तान में 11 वर्षों में हुआ पहला आम चुनाव जीता।
- भारतीय मूल के वासुदेव पाण्डे त्रिनिदाद एवं टोबैगो के 1995 ने प्रधानमंत्री बने।
- चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता जिंग शेंग 1997 में 18 वर्ष बाद रिहा किये गए।
- कनाडा ने 1998 में अपना यहाँ नागरिकता कानून को सख्त बनाया।
- सन 2000 में रूस द्वारा अंतरिक्ष केन्द्र मीर को डुबाने का फैसला।
- अफ़गानिस्तान 2001 में हेतु संयुक्त राष्ट्र के 21 सदस्यीय दल में भारत शामिल।
- मुशर्रफ़ ने 2002 में पांच साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- पाकिस्तान ने 2006 में मध्यम दूरी के गौरी-V मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफ़ान 'सीडर' ने 2007 में बांग्ला देश में भीषण तबाही मचाई।
- वन टू गो एयरलाइंस का विमान 2007 में थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत।
- स्टेट बैंक की हेवरा के 2008 में 58 लाख रुपये की कर्ज़ माफ़ की।
- चन्द्रयान के लूनर लेजर रेंजिंग उपकरण ने 2008 से सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया।
- वाशिंगटन में 2013 में एक बंदूकधारी ने नौसेना के एक शिविर में 12 लोगों की गोली मारकर हत्या की।
- मुंबई में सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही 2013 में भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी।

विशेष आलेख

ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लागू करने में बाधाएँ

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा एक निरंतर संघर्ष है। लाखों लोग चिकित्सा देखभाल तक सीमित पहुँच के साथ रहते हैं, न केवल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की अनुपस्थिति का सामना करते हैं, बल्कि पुराने बुनियादी ढांचे के बोझ का भी सामना करते हैं। ये केवल चुनौतियाँ नहीं हैं-ये देरी से होने वाले उपचार और रोकथाम योग्य बीमारियों के पीछे के कारण हैं जो जीवन पर भारी पड़ रहे हैं।

प्रियंका सौरभ

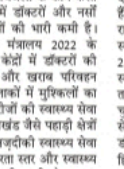

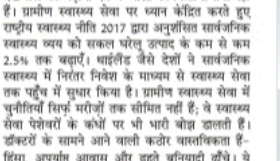

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की नींव होती है, खासकर ग्रामीण भारत में, जहाँ 65प्रतिशत से ज्यादा आबादी रहती है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ देने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा : ज्यादातर ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में बिजली, स्वच्छ पानी और उपकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021 के अनुसार, 8प्रतिशत से ज्यादा स्वास्थ्य सेवा केंद्र बिना बिजली के काम करते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में डॉक्टरों और नर्सों सहित प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2022 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में डॉक्टरों की 23प्रतिशत कमी है। लंबी दूरी और खराब परिवहन नेटवर्क के कारण दूरदराज के इलाकों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे मरीजों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रभावित होती है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के 40प्रतिशत से ज्यादा गाँवों में नजदीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक पहुँच नहीं है। कम साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का कम उपयोग होता है। बिहार जैसे राज्यों में कम जागरूकता के कारण टीकाकरण दर कम बनी हुई है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.3प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023), जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अपर्याप्त है।

पीएचसी में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, बिजली, स्वच्छ पानी और आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने में निवेश करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त धन आवंटित कर सकता है। डॉक्टरों और नर्सों के लिए उच्च वेतन, आवास और ग्रामीण भत्ते जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से भर्ती और प्रतिधारण को बढ़ाएँ। तमिलनाडु जैसे राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण सेवा लाभ प्रदान करते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों के उपयोग का विस्तार करें। ग्रामीण भारत में टेलीकंसल्टेशन प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। मातृ और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समुदाय-आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ। ग्रामीण इलाकों में मातृ देखभाल को बढ़ावा देने में आशा कार्यकर्ता प्रभावी रही हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसित सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2.5% तक बढ़ाएँ। थाईलैंड जैसे देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में निरंतर निवेश के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियाँ सिर्फ मरीजों तक सीमित नहीं हैं; वे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के कंधों पर भी भारी बोझ डालती हैं। डॉक्टरों के सामने आने वाली कठोर वास्तविकता हैं- हिंसा, अपर्याप्त आवास और डहते बुनियादी ढाँचे। ये कारक यहाँ सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए कई लोगों को रोकते हैं। विशेषज्ञों को लाने के प्रयासों के बावजूद, ऐसे पेशेवरों की कमी का मतलब अक्सर यह होता है कि मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक चेतावनी थी, फिर भी इस क्षेत्र में कोई अतिरिक्त निवेश नहीं हुआ है। सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, ग्रामीण भारत के लोग, विशेष रूप से पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में रहने वाले लोग, बीमारी का सामना करने पर खुद का खयाल रखना जारी रखते हैं-अक्सर बीमारी के गंभीर होने तक देखभाल में देरी करते हैं, बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते हैं या अनौपचारिक, खराब गुणवत्ता वाले प्रदाताओं से देखभाल लेते हैं। जब वे स्वास्थ्य सेवा लेने में सक्षम होते हैं, तब भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें खराब गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिलती है और अक्सर इस प्रक्रिया में वे कर्ज में डूब जाते हैं। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को पहुँच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण, टेलीमेडिसिन, अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों की उपलब्धता को सरीखित करना, यह सुनिश्चित करना कि रोगियों को इंटरनेट और बिजली जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे तक पहुँच हो।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,झालरापुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पालन*। प्रधान संपादक-राव विजय विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-गेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-ज्ञानवी सेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

खरीफ में कैसी रहेगी महंगाई

आने वाले महीनों में महंगाई कैसी रहेगी इसके लिए अब सभी की नजरें खरीफ फसल पर है

छायांकन- अजय मोहंती

संजीव मुखर्जी

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में 14 महीने के उच्च स्तर 6.2 फीसदी पर पहुंच गई। इसी तरह थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई अक्टूबर में बढ़कर चार माह के उच्च स्तर 2.36 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसका बड़ा कारण खाद्य कीमतों में तेजी थी। आने वाले महीनों में महंगाई कैसी रहेगी इसके लिए अब सभी की नजरें खरीफ फसल पर है।

इस दौरान सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल देखी गई क्योंकि इस बार मॉनसून भी लंबे समय तक रहा और झमाझम बारिश हुई, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अब सब्जियों की कीमतों में कमी आएगी। नई आवक के बाद प्याज के दाम भी घटेंगे।

कैसा रहेगा उत्पादन

कुछ हफ्ते पहले जारी 2024-25 खरीफ सत्र के पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, हाल ही में खत्म हुए खरीफ सत्र में चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 12 करोड़ टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले 5.9 फीसदी अधिक है। रकबा बढ़ने, लंबे समय तक मॉनसून के रहने और अनुकूल कीमतों के कारण इस बार चावल के उत्पादन को बल मिला है।

कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पहली बार खरीफ सत्र में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया है, जिसने धान के रकबे का सटीक आकलन किया है, इसलिए ही कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

चावल की अच्छी कीमतों के कारण कुछ किसानों ने इस साल दलहन और कपास की खेती छोड़ धान की ओर रुख कर लिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) के आधार पर मापी जाने वाली चावल की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले वर्ष (अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024) में अधिकतर दो अंकों में रही। चावल के बेहतर उत्पादन से निर्यात को बढ़ावा देने और प्रतिबंधों में ढील देने में मदद मिल सकती है।

मक्का

पहले अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि इस बार मक्का उत्पादन पिछले सत्र से करीब 10.3 फीसदी बढ़कर 2.45 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। इससे कीमतें कम करने में मदद मिलेगी और अनाज आधारित एथनॉल विनिर्माताओं सहित उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

आईसीन इंडिया के जिंस विश्लेषक राहुल चौहान ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'मक्का बाजार में एथनॉल उद्योग और स्टार्चकिस्टों के मक्के पर पकड़ से इसकी मजबूत मांग दिखती है, जिससे कीमतें स्थिर या फिर अधिक होती हैं। भारत में रिकॉर्ड उत्पादन का बाजार पर कोई खास असर नहीं दिखा है क्योंकि अधिकतर उपज को निजी खरीदारों ने खरीद लिया है। स्थानीय कीमतों से घट-बढ़ से पता चलता है कि भले ही मांग दमदार है मगर इलाके के अनुसार इसमें बदलाव आता है और कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक होने के कारण सरकार की भूमिका भी इसमें कम हो जाती है।' उन्होंने कहा कि कीमतें तब तक स्थिर अथवा अधिक रहेंगी जब तक एथनॉल की मांग नहीं बदलती है, सरकार नीति में बदलाव नहीं किया जाता है अथवा अंतरराष्ट्रीय मक्का उत्पादन खासकर ब्राजील से उसमें भारी बदलाव नहीं आता है।

अगर हम दालों की बात करें तो इस बार दलहन उत्पादन 69.5 लाख तक गिरने की उम्मीद है और ऐसा उड़द के उत्पादन में कमी के कारण होगा।

देश में फसल उत्पादन

खरीफ फसल उत्पादन (आंकड़े मिलियन टन में) *

	2023-24**	2024-25#	% बदलाव
चावल	113.25	119.93	5.9
मक्का	22.24	24.54	10.3
ज्वार	1.5	2.19	46.0
बाजरा	9.66	9.37	-3.0
रागी	1.67	1.39	-16.8
कुल अनाज	155.76	164.7	5.7
कुल दलहन	6.97	6.95	-0.3
उड़द	1.6	1.2	-25.0
मूंग	1.15	1.38	20.0
मूंगफली	8.66	10.36	19.6
सोयाबीन	13.06	13.36	2.3
कुल तिलहन	24.16	25.74	6.5
गन्ना	453.15	439.93	-2.9
कपास***	32.52	29.92	-8.0
जूट##	9.69	8.45	-12.8

*पहला अग्रिम अनुमान, ** अग्रिम अनुमान के अनुसार, *** मिलियन बेल, 1 बेल-170 किलोग्राम, ## मिलियन बेल- 1 बेल-180 किलोग्राम, # पहला अग्रिम अनुमान, नोट - कुल आंकड़े मिलान नहीं होंगे क्योंकि इसमें सभी फसलों को शामिल नहीं किया गया है, स्रोत- भारत सरकार

उड़द

पिछले सत्र के 16 लाख टन के मुकाबले इस साल खरीफ सत्र में उड़द का उत्पादन 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचने का खतरा है और आशंका जताई जा रही है इस साल 12.1 लाख टन ही उत्पादन हो सकता है। यह पिछले कई वर्षों के मुकाबले बड़ी गिरावट है, जब साल 2015 में 12.5 लाख टन उड़द का उत्पादन हुआ था और साल 2017 में सर्वाधिक 27.5 लाख टन उड़द की उपज हुई थी।'

गिरावट का बड़ा कारण बोआई क्षेत्र में कमी है और महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख उड़द उत्पादक राज्यों में किसानों ने संभवतः बेहतर रिटर्न की आस में अरहर जैसी अन्य फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है।

घरेलू उत्पादन में कमी की भरपाई के लिए भारत बड़े पैमाने पर उड़द का आयात कर रहा है। इस साल अप्रैल और अक्टूबर के बीच आयात करीब 43 फीसदी बढ़ गया। भारत में उड़द की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जो स्थानीय उत्पादन में कमी के कारण घरेलू आपूर्ति में कमी दर्शाता है। वैश्विक कीमतें भी अस्थिर रही हैं।

अरहर

बीते कुछ वर्षों में अरहर के उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। अरहर का उत्पादन साल 2020 के 43.2 लाख टन से कम होकर साल 2022 में 33.1 लाख टन रह गया। पिछले साल की खरीफ सत्र में उत्पादन मामूली बढ़कर 34.2 लाख टन हो गया था और इस साल पहले अनुमानों के के मुताबिक उत्पादन 35 लाख टन होने की उम्मीद है। यह दर्शाता है कि वर्षों की गिरावट के बाद उत्पादन स्थिर हो सकता है।

व्यापारियों का कहना है कि कर्नाटक से नई अरहर की आवक शुरू हो गई है और जनवरी-फरवरी में नए माल की आवक के साथ ही आने वाले महीनों में अरहर की अधिक उपलब्धता होगी। दिसंबर के बाद भारत में आवक चरम पर हो सकती है, जिससे निकट भविष्य में बेहतर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, कीमतें लगातार एमएसपी से अधिक बनी हुई हैं, लेकिन यह अगले कुछ महीनों में कम हो सकता है क्योंकि नई फसल का आगमन शुरू हो जाएगा और फिर दिसंबर के बाद से आवक चरम पर होने की उम्मीद है। इससे कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन म्यांमार से आयात और निर्यात की स्थिति महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी। पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, साल 2024 के खरीफ सीजन में खाद्यान्न का उत्पादन 16.47 करोड़ टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले खरीफ सत्र के मुकाबले 5.7 फीसदी ज्यादा है।

तिलहन

अन्य फसलों में मूंगफली और सोयाबीन के मजबूत उत्पादन से तिलहन उत्पादन 6.5 फीसदी बढ़कर 2.57 करोड़ टन होने का अनुमान है।

मूंगफली और सोयाबीन

इस साल के खरीफ सत्र में मूंगफली का उत्पादन 1.03 करोड़ टन यानी पिछले साल के मुकाबले 19.6 फीसदी अधिक होने की उम्मीद है। सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के 1.30 करोड़ टन से बढ़कर 1.33 करोड़ टन रहने की संभावना है। इस बार घरेलू उत्पादन मजबूत रहने से आयातित खाद्य तेलों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। बुधवार को बयान जारी कर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अनुमान जताया है कि नवंबर में शुरू हुए 2024-25 तिलहन विपणन वर्ष में खाद्य तेल का आयात 10 लाख टन कम होकर 1.5 करोड़ टन रह सकता है। इसकी वजह दमदार फसल की उम्मीद है।

मगर किसानों के लिए यह ज्यादा खुशखबरी नहीं है क्योंकि तिलहन की कीमतें खासकर सोयाबीन और मूंगफली के लिए बड़े पैमाने पर अपने एमएसपी से कम हैं। इसमें चुनावी राज्य महाराष्ट्र भी शामिल है, जो सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है।

स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर कीमतों को बढ़ाने के लिए किसानों से एमएसपी पर मूंगफली और सोयाबीन की खरीदारी शुरू की है। मूंगफली के खरीद का लक्ष्य 17.4 लाख टन, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात (11.3 लाख टन) और राजस्थान (5.03 लाख टन) से आएगा। व्यापारियों का कहना है कि बाजार की कम कीमतों को देखते हुए सरकार की खरीद बढ़ सकती है, जिससे भविष्य में कीमतें कम होने में मदद मिलेगी। सोयाबीन के मामले में भी सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से सक्रिय तौर पर खरीद रही है।

चुनावी राज्य महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता कम खरीद के मुद्दे को हवा दे रहे हैं और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कम कीमतों के बावजूद किसानों को अपना काम खुद करने दिया जा रहा है।

अन्य फसलें

पहले अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि इस साल गन्ना उत्पादन 43.99 करोड़ टन रहेगा, जो पिछले साल के मुकाबले 3 फीसदी कम है। इसके लिए मौजूदा निर्यात प्रतिबंध को बरकरार रखना जरूरी हो सकता है।

कपास का उत्पादन भी करीब 8 फीसदी कम होकर 2.99 करोड़ गांठ होने की आशंका है। एक गांठ 179 किलोग्राम के बराबर होता है। कपास के उत्पादन में यह गिरावट बार-बार कीटों के हमले और घटती पैदावार के कारण रकबे में आए भारी बदलाव के कारण है।

यह काफी चिंता की बात है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रारंभिक आकलन दर्शाते हैं कि भारत को पिछले साल के मुकाबले इस बार 43 फीसदी ज्यादा आयात करना पड़ सकता है। इसी तरह, कपास का उत्पादन कम होने की वजह से साल 2024-25 में निर्यात में भी 37 फीसदी की कमी आ सकती है।

रबी बोआई

जलाशयों में पर्याप्त जल

संजीव मुखर्जी

जैसे ही आगामी हफ्तों में गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी फसलों की बोआई में तेजी आएगी इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता जलाशयों में जलस्तर होगा। खासकर जिनके पास सिंचाई क्षमता होती है। केंद्रीय जल आयोग के 7 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार द्वारा निगरानी किए गए देश के 155 जलाशयों में जलस्तर उनके पूर्ण स्तर का करीब 86 फीसदी था, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले काफी ज्यादा है और साल की इसी अवधि से सामान्य स्तर पर भी है। मगर उत्तर भारत के 11 पुराने जलाशयों में जलस्तर पिछले साल के मुकाबले कम है और सामान्य स्तर से भी कम है। साथ ही मॉनसून में देरी के साथ मिट्टी की नमी भी अच्छी होनी चाहिए।

कृषि मंत्रालय के आकलन के मुताबिक, इस साल 25 से 31 अक्टूबर के दौरान जड़ वाले स्थान पर मिट्टी की नमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से, दक्षिण बिहार में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में बीते नौ वर्षों के औसत से बेहतर है अथवा वैसा ही है। जबकि, ये बिहार के उत्तरी इलाकों, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बीते नौ वर्षों के औसत से कम है। इस बीच, 15 नवंबर तक देश में मॉनसून के बाद की बारिश औसत से करीब 9 फीसदी कम रही और 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में सर्वाधिक 75 फीसदी कम बारिश हुई।

देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कृषि की घटती हिस्सेदारी

गरीबी खत्म करने और लोगों की आय बढ़ाने का रास्ता लाभकारी रोजगार के जरिये ही है। मगर प्रौद्योगिकी में आए नवाचार ने उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मानव श्रम की तैनाती को नुकसान पहुंचाया है

रामेश चन्द

विकास में कृषि की भूमिका संबंधी तमाम दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कृषि की घटती हिस्सेदारी को दर्शाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के निम्न आय से मध्य एवं उच्च आय की ओर रुख करने के साथ ही इसकी रोजगार में हिस्सेदारी में गिरावट का भी पता चलता है। इसी आधार पर वृद्धि एवं विकास के लिए बनाई जा रही नीतियों में भी अब गैर कृषि क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण पर जोर दिया जा रहा है।

इस विचार की जड़ ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर लुईस (1954) के काम में दिखती है। उन्होंने आर्थिक विकास का वर्णन वृद्धि की उस प्रक्रिया के तौर पर किया है जिसके तहत संसाधन कम उत्पादकता एवं पारंपरिक तकनीक वाले कृषि क्षेत्र से अधिक उत्पादकता वाले आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं। यह सिद्धांत आर्थिक विकास में कृषि की काफी निष्क्रिय भूमिका बताता है, लेकिन औद्योगीकरण का समर्थन करने वाले कई विकासशील देश बड़े पैमाने पर अपने उद्योगों को सहारा देने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं।

हरित क्रांति के बाद विकास के लुईस मॉडल की कुछ धारणाओं का खंडन किया गया। पहले, हरित क्रांति से पता चला कि प्रौद्योगिकी कृषि को आधुनिक बनाने और उद्योग की कल्पना के अनुसार अधिशेष पैदा करने में महती भूमिका निभा सकती है। दूसरा, खेती में श्रम की असीमित आपूर्ति की धारणा भी अब मान्य नहीं रही है। इन बदलावों का कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक बदलाव के मॉडल पर असर पड़ता है।

हालिया अनुभव

विकासशील और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के मामले में बीते तीन से चार दशकों का अनुभव दर्शाता है कि कार्यबल को कृषि से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया काफी धीमी है और ये सुचारु भी नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी कृषि की हिस्सेदारी में काफी तेजी से गिरावट देखी जा रही है जबकि रोजगार हिस्सेदारी में काफी कम गिरावट आई है।

यह आर्थिक बदलाव एवं विकास के विभिन्न चरणों में बड़ी संख्या में देशों के अनुभव से देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर सन् 1991 से 2021 के बीच तीन दशकों के दौरान प्रति व्यक्ति जीडीपी (साल 2015 में डॉलर में मापा गया) चीन में 10 गुना से ज्यादा, वियतनाम में 4.8 गुना, भारत में 3.4 गुना और इंडोनेशिया में 2.4 गुना बढ़ गया। मगर इससे कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता (प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित) पर असर नहीं पड़ा।

इन चार उभरते देशों में कृषि एवं गैर गैर कृषि के बीच प्रति कर्मचारी उत्पादकता अथवा आय में सबसे ज्यादा असमानता चीन में देखने को मिली, जहां बीते तीन दशकों में प्रति व्यक्ति आय और विनिर्माण उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज किया गया है। चीन में खेती करने वाला श्रमिक गैर कृषि श्रमिक की आय का सिर्फ एक चौथाई ही कमा पाता है। भारत और वियतनाम में भी चीन जैसी ही स्थिति है, लेकिन इंडोनेशिया में कम असमानता है। इन अनुभवों से पता चलता है कि गैर कृषि अथवा तथाकथित आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में तेज वृद्धि से कृषि कार्यबल में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ है। नतीजतन, रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के उत्पादन अथवा आय में इसकी हिस्सेदारी से बहुत ज्यादा रही। ये चीन में तीन गुना, भारत और वियतनाम में ढाई गुना तथा इंडोनेशिया में दोगुना से अधिक रही।

ढांचागत बदलाव के पारंपरिक मॉडल के कुछ अन्य विरोधाभास भी हैं। जैसे- पहला, दक्षिण अफ्रीका में प्रति व्यक्ति आय और विकास के काफी उच्च स्तर पर प्रति कामगार आय में सर्वाधिक असमानता भी दर्शाता है। वहां का एक कृषि श्रमिक गैर कृषि श्रमिक की आय के दसवें हिस्से से भी कम कमाता है। दूसरा, कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों में और पूरे विश्व में हाल के समय में बढ़ी है।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विनिर्माण और गैर कृषि गतिविधियों की ओर ढांचागत बदलाव सभी क्षेत्रों में उत्पादकता में व्यापक अंतर और कृषि में कम आय को पूरी तरह ठीक करते हैं। यह लुईस मॉल और इस मॉडल पर आधारित आर्थिक विकास के सिद्धांतों के ठीक उलट है। इसका बड़ा कारण विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं।

गरीबी और अन्य विकास लक्ष्य

दमदार साक्ष्यों से विकासशील देशों में गरीबी में कमी और समग्र विकास के लिए कृषि की वृद्धि के बारे में पता चलता है। भारत के मामले में राज्यस्तरीय आंकड़ों पर आधारित विश्लेषणों से पता चलता है कि भूमि उत्पादकता अथवा खेती में श्रमिक उत्पादकता जैसे किसी भी संकेतक से मापा गया कृषि विकास, ग्रामीण के साथ-साथ कुल गरीबी पर भी काफी असर करता है।

गरीबी उन्मूलन और लोगों की आमदनी बढ़ाने का सीधा रास्ता रोजगार ही है। मगर रोजगार हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है। रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफीशल इंटेलिजेंस, एआई आदि जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकियों से कुछ हद तक श्रमिकों की जरूरतों को कम करते हुए पूंजी गहन उत्पादों का रुख कर रहे हैं।

स्थिरता और जलवायु परिवर्तन भी लोगों के जीवन और ग्रह के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि में होता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, भारत में उपयोग होने वाले कुल पानी का 80 से 90 फीसदी खेती में उपयोग किया जाता है जबकि इसका वैश्विक औसत 70 फीसदी है। अभी भी खेतों के 50 फीसदी से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई नहीं हो पाती है। देश के लगभग सभी राज्यों में भूजल संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। भारत की करीब आधी जमीन खेती के उपयोग के लिए है और इसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। इसलिए, जिस तरह से खेती का जाती है उससे मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता निर्धारित होती है। पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए काफी कम क्षेत्र ही मौजूद है। गैर कृषि उपयोगों के लिए की जमीन की जरूरतों को पूरा करने और टिकाऊ भूमि के समाधान के लिए भी कृषि में उच्च उत्पादकता की जरूरत होती है।

वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि की हिस्सेदारी वैश्विक उत्पादन और आय में हिस्सेदारी से कहीं ज्यादा बताई गई है। भारत में कृषि को कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 14 फीसदी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि, कृषि गतिविधियों से होने वाला उत्सर्जन भी अमूमन दिखाई नहीं देता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एवं साफ हवा, जमीन और पानी के टिकाऊ उपयोग के केंद्र में कृषि है। कृषि, जलवायु परिवर्तन एवं स्थिरता के लिए समस्या और समाधानना दोनों का हिस्सा है। सभी क्षेत्रों में कृषि हरित वृद्धि के लिए सबसे बेहतर उम्मीद है और यह पर्यावरण के नजरिये से टिकाऊ भी है।

स्वास्थ्य एवं पोषण

खाने की गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ता तेजी से जागरूक हो रहे हैं और विशिष्ट खासियत वाले खाद्य पदार्थों को तरजीह दे रहे हैं। खाना और स्वास्थ्य एवं रोगप्रतिरोधक क्षमता के बीच मजबूत संबंध पर भी जागरूकता फैल रही है। इसके लिए अच्छी तरह से तैयार की गई आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच सीधे संबंधों के जरिये मांग को आपूर्ति के साथ जोड़ने की जरूरत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रखने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए खाने के चिकित्सीय मूल्यों और इसके उचित उपयोग के प्रति भी लोगों की रुचि शुरू हुई है। नतीजतन, विशिष्ट गुणों वाले औषधीय पौधे और किस्मों की मांग में इजाफा हो रहा है। कुछ उद्यमी ऐसे उत्पाद देने के लिए नए मूल्य श्रृंखलाओं के जरिये ग्राहकों और उत्पादकों को जोड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे उत्पादों की आपूर्ति के लिए ट्रेसिबिलिटी और लेबलिंग के साथ मूल्य श्रृंखला भी बनाने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, खाने की मांग में आए इन बदलावों से नए प्रकार की खेती का अवसर आया है, जो क्षेत्र के भीतर ही अधिक आकर्षक और अधिक भुगतान वाला रोजगार दे सकता है।

कृषि केंद्रित समावेशी विकास

गरीबी खत्म करने और लोगों की आय बढ़ाने का रास्ता लाभकारी रोजगार के जरिये ही है। मगर प्रौद्योगिकी में आए नवाचार ने उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मानव श्रम की तैनाती को नुकसान पहुंचाया है। नतीजतन, कार्यबल को कृषि से इतर स्थानांतरित करने में अभी काफी वक्त लगेगा। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी काफी अधिक बनी हुई है। चीन में भी ऐसा ही अनुभव किया गया है। इससे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी खेती को लंबे समय तक रोजगार के मुख्य स्रोत के तौर पर जारी रखना होगा।

इसके लिए कृषि और उसके आसपास नई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और कृषि की नौकरियों को और ज्यादा आकर्षक बनाने की दरकार है। इसके लिए बीज से बिक्री तक कृषि के आधुनिकीकरण और उत्पादन के साथ-साथ अंतिम उपयोग के बीच करीबी संबंध बनाना होगा। वहीं उत्पादन के मोर्चे पर, इसमें उच्च तकनीक, उच्च उत्पादकता और ज्ञान एवं कौशल आधारित गहन खेती भी शामिल करनी होगी। इसके अलावा, खेतों पर मूल्यवर्धन की भी काफी गुंजाइश है। खाने में लोगों की प्राथमिकताओं में ताजगी, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अद्वितीय गुण शामिल हो रहे हैं। वहां तक कि गैर खाद्य में भी विकल्प सिंथेटिक्स और रासायनिक उत्पादों से बायोस की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे मौकों को भुनाने के लिए कई कृषि स्तरीय कुटीर उद्योग भी तैयार किए जा सकते हैं।

कृषि आधारित आर्थिक बदलाव का दूसरा रास्ता जैव प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष से भी संभव है। पादप जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति से स्वास्थ्य, फार्मा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन भी संभव हो रहा है। नौकरियों पर डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रतिकूल प्रभाव का बोलबाला पादप जैव प्रौद्योगिकी से लिया जा सकता है। इससे फसलों का विकास होता है।

आर्थिक विकास का संदर्भ भी अब बदल गया है क्योंकि रोजगार, स्थिरता, पर्यावरण सेवा, गरीबी, पोषण और स्वास्थ्य आज के समय की बड़ी चिंता बन गई हैं। इस बदलते संदर्भ में कृषि को विकास अर्थशास्त्र में प्रमुख सोच के मुकाबले कहीं अधिक बड़ी और अलग भूमिका निभाते हुए देखा जाता है।

(लेखक नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के सदस्य हैं। उनके विचार निजी हैं।)

चिंतन

बच्चों के लिए सोशल मीडिया को सीमित करने की जरूरत

ऑस्ट्रेलिया सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके बाद से बहस तेज हो गई है कि क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार के पास इस बात के पर्याप्त तथ्य हैं कि बच्चों, किशोरों और युवाओं में सोशल मीडिया के प्रति दीवानगी के चलते उनके मानसिक स्वास्थ्य व मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है? इस प्रतिबंध के आलोक में व्यापक पैमाने पर सार्वजनिक बहस जारी है, जिसमें शिक्षाविद्, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ व संगठन, समर्थन करने वाले समूह और डिजिटल शिक्षा प्रदाता शामिल हैं। चूंकि सोशल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न मौजूं हैं कि क्या प्रतिबंध लगाना ठीक है? क्या इसका कोई और विकल्प है? क्या सोशल मीडिया की लत किशोर व युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर व बीमार बना रही है? ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के तहत स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज के अध्ययन के मुताबिक, सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से बच्चों, किशोरों व युवाओं को नुकसान पहुंचने के विश्वसनीय प्रमाण हैं। इसलिए नुकसान है कि नहीं, इस विषय पर बहस का औचित्य ही नहीं है, विमर्श इस विषय पर होना चाहिए कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व किशोरों को किस तरह से सोशल मीडिया की लत से बचाया जा सकता है, इन्हें कैसे स्मार्ट गजट से दूर रखा जा सकता है? भारत में भी यह गंभीर समस्या है। क्या भारत में भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून लाया जाना चाहिए? हाल के वर्षों में, बच्चों और युवाओं में चिंता एवं घबराहट की समस्या बढ़ रही है, उदासी व छूट जाने का डर या फोमो के सिंड्रोम बढ़े हैं, वे अत्यधिक आत्मकेंद्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया में डूबे रहने वालों में नींद न आना, फ्रोकस कम होना, एक्सरसाइज न करना, डिप्रेशन, मानसिक अशांति, अत्यधिक चिंता, जुनूनी-बाध्यकारी विकार (ओसीडी), एटेंशन डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (विकार) (एडीएचडी), निगेटिविटी जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। किसी भी लत में डोपामाइन नामक कैमिकल रिलीज होता है, जिससे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिव होता है और अच्छा महसूस होता है। हालांकि, जब लाइक्स या कमेंट्स नहीं मिलते, तो इससे स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ती है। सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी साइटों के उपयोग से जुड़े 46 हानिकारक प्रभावों की जानकारी दी है। इनमें से चिंता, अवसाद, परेशान किया जाना, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले विचार, साइबर स्टॉकिंग, अपराध, ईर्ष्या, सूचना अधिभार और ऑनलाइन सुरक्षा की कमी आदि शामिल हैं। ऑनलाइन नफरत, सेक्सटिंग, फ्रेक जानकारी, अनुचित सामग्री, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी आदि सोशल मीडिया के खतरे हैं। इसके गहन इस्तेमाल से मानव मस्तिष्क में न्यूरोनल संरचनाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। स्क्रीन पर नजरें गड़ाने के चलते आंखों की रोशनी की समस्या भी बढ़ रही है। अब तक हुए अनेक अध्ययन के बाद पर्याप्त सबूत हैं कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। अब इस बात पर सहमत होने का समय आ गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों, किशोरों व युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसके उपयोग को लेकर सख्त एवं उचित विनियमन की आवश्यकता है।

सहकारी सम्मेलन

सुभाष चन्द्र

सहकारिता से खुलेगी समृद्धि की राह

सहकारी समितियों की उपलब्धता बढ़ाने, क्षमता निर्माण के माध्यम से उनके विकास को बढ़ावा देने और उनकी पारस्परिक साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में आईसीए ठोस कदम बढ़ा रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी की बागडोर विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था इफको समेत देश की 17 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के हाथों में है। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के भारत में आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ''सहकार से समृद्धि का विचार अब पूरे विश्व में फैलेगा। इस वैश्विक सम्मेलन का थीम 'सहकारिताएं- सबकी समृद्धि का द्वार' तय किया गया है। सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।

भारतीय सहकारिता की मजबूत स्थिति को देखते हुए वैश्विक सहकारी आंदोलन के प्रमुख निकाय के रूप में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) की महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25-30 नवंबर तक भारत द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। आईसीए की स्थापना (1895) के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह आयोजन भारत में होने जा रहा है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य रहा है। आईसीए दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें सेवाएं प्रदान करता है। आईसीए सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष वैश्विक संस्था है, जिनकी संख्या दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा है।

विश्व में 107 देशों के 310 से अधिक संगठन अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के सदस्य हैं। सहकारी समितियों की उपलब्धता बढ़ाने, क्षमता निर्माण के माध्यम से उनके विकास को बढ़ावा देने और उनकी पारस्परिक साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में आईसीए ठोस कदम बढ़ा रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी की बागडोर विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था इफको समेत देश की 17 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के हाथों में है। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के भारत में आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ''सहकार से समृद्धि का विचार अब पूरे विश्व में फैलेगा। इस वैश्विक सम्मेलन का थीम सब्जेक्ट ''सहकारिताएं- सबकी समृद्धि का द्वार'तय किया गया है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी हो रहा है। इस सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने 'हाट'में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जा रहा है। भारत में सहकारिता की ताजा पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है।

भारत सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दर्जनों महत्त्वपूर्ण बदलावों के माध्यम से इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए नए मंत्रालय का गठन किया गया। थम सी गई सहकारिता को आगे बढ़ाने का दायित्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में सौंपा गया जिसका नतीजा सबके सामने है। सहकारी क्षेत्र के संस्थानों के पुनर्गठन और निष्क्रिय हो चुकी प्राथमिक सोसाइटियों में जान फूंक दी गई। मॉडल बायलॉज से प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) को ताकत दी गई और उसके कामकाज के दायरे को बढ़ाया गया। सहकारिता पर लागू टैक्स को तर्कसंगत बनाया गया। सहकारी चीनी उद्योग और टेक्सटाइल से लेकर डेयरी और फिशरीज (दुग्ध और मत्स्य) क्षेत्र को सबल बनाया गया है। राज्यों के साथ समन्वय बनाकर सहकारिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय इन्हीं पहलों को जाता है। आईसीए की इस पहल से दुनिया के दूसरे देशों को भारत के सहकारी आंदोलन से बहुत कुछ

सीखने को मिलेगा। भारत भी उनके अनुभवों का लाभ उठा सकेगा। दुनिया में लगभग 30 लाख सहकारी समितियां हैं जिनमें से करीब 8 लाख सहकारी समितियां यानी एक चौथाई से अधिक समितियां भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक लोग इन समितियों के सदस्य हैं जिनमें से 29 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारत के हैं।

सहकारिता क्षेत्र ने दुनियाभर में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। सहकारी समितियों की संख्या और उनके विस्तार की संभावनाओं के मामले में भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत में सहकारिता के व्यापक फलक को विस्तार दिया गया है, जिससे सहकारी समितियों की संख्या और साथ ही सहकारिता से जुड़े सदस्यों में वृद्धि हुई है। भारतीय सहकारी प्रणाली में सबसे बड़ा परिवर्तन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के मॉडल बायलॉज का कार्यान्वयन है। भारत में पैक्स के कंप्यूटरीकरण का अभियान और शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी संस्थाओं से इन्हें जोड़ने के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य बड़ी पहलों के साथ ही अनेक सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। सहकारिता क्षेत्र में तीन नई राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी समितियों : राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के गठन ने भारत को वैश्विक सहकारिता आंदोलन में अग्रणी बना दिया है। इन सुधारों के साथ भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। भारत की इन पहलों ने दुनिया के दूसरे देशों का ध्यान खींचा है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान जहां संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित लक्ष्य को सहकारिता के माध्यम से पूरा करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, वहीं सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन में इन सभी लक्ष्यों पर व्यापक चर्चा कराई जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को गति देने में भारतीय सहकारी समितियां सक्रिय हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ वैश्विक चिंताओं को दूर करने को लेकर तैयार बिंदुओं पर गंभीर विचार-विमर्श किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 सतत विकास लक्ष्य चिन्हित किए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सहकारी समितियों की सर्वभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इनमें पारिस्थितिकी संतुलन, स्थिर आजीविका, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास एवं सहयोग, मिट्टी की सेहत एवं जीवन, महिलाओं का सशक्तिकरण सहित प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार आदि विषयों को शामिल किया गया है। वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाये जाने का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। इसमें सहकारी क्षेत्र की भूमिका पहले ही निर्धारित कर दी गई है जिससे इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है। गौरतलब है कि दूध और चीनी से लेकर दैनिक जरूरत की हर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहकारी समितियां आगे बढ़ रही हैं। दरअसल सहकारिता मानव जीवन के उत्थान के लिए नैसर्गिक रूप से व्यवहार में लाई गई वह कार्यसंस्कृति है, जिसमें सबकी भागीदारी को वरीयता दी जाती है। इस व्यवस्था में अभावग्रस्त और शोषित वर्ग को मालिकाना हक के साथ आर्थिक प्रकल्प संचालित करने की सुविधा मिलती है। उम्मीद है कि सहकारिता की दुनिया में एक नई सुबह आएगी, जो सहकार के आत्मा यानी संस्कार, सर्वोदय और समन्वय के जरिये वंचित वर्ग के आर्थिक और सामाजिक उद्धार पर केंद्रित हो।

(लेखक राज्यसभा सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

चर्चा में

डॉ. रमेश ठाकुर

भारत का 'लेखक गांव' बना साहित्य मनीषियों की पसंद

ग्लोबल स्तर पर प्रचलित हुआ 'लेखक गांव' न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि समूचे संसार में इस समय चर्चाओं में है। ये अनोखा गांव हिमालयी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता की कोख उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मात्र 40-50 किमी दूरी पर बसा है। गांव चर्चाओं के केन्द्र में इसलिए है कि वहां साहित्यक मनीषियों, रचनाधर्मियों, साधकों, लेखकों, पत्रकारों व रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े बुद्धिजीवियों की सभी मुकम्मल जरूरत पूरी होती है। लेखनी का संपूर्ण वातावरण गांव अपने में समेटा हुआ है। पूर्व में गांव का नाम 'थानो' था जिसे कुछ समय पहले राज्य सरकार ने 'लेखक गांव' में तब्दील कर दिया है जो अब रचनाधर्मी समुदाय के लिए तीर्थ के रूप में विकसित है। गांव में लेखक-साहित्यकार शांत मन से प्रकृति की गोद में बैठकर अपनी रचनाओं को आकार देंगे। ये गांव करीब 50-60 बीघे में फैला हुआ है। लेखकों के लिए कुटीर, पुस्तकालय, पठन-पाठन सामग्री, योगासन व रहने-खाने की तमाम व्यवस्थाओं के अलावा रचना कर्मियों के लिए उपयुक्त वातावरण भी स्थापित किया गया है। साहित्य संवेदनाओं को सहेजने का मादा रखने वाला ये 'लेखक गांव' चर्चाओं में इसलिए है, क्योंकि पिछले माह यानी अक्टूबर में ही वहां तीन दिनी 'अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव 2024' का शानदार आयोजन हुआ जिसमें भारतीय साहित्यकारों के अलावा 55 से अधिक देशों के लेखक, पत्रकार, विचारक, चिंतक, साधक, शोधकर्मी और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। 'कला महोत्सव' के नाम पर देखभूमि पर लगे पहले इस जमावड़े ने सभी का ध्यानाकर्षण करवाया है। हालांकि, गांव को बसाने की परिकल्पना कई वर्ष पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व साहित्यकार रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने की थी, जो कहीं अब जाकर साकार हुई है। 'निशंक' को हमेशा से साहित्य विधा का बड़ा प्रयोगधर्मी माना गया है। गांव के विकास के लिए बड़ी रकम प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित हो चुकी है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है, पहला चरण तकरीबन पूरा होने को है। हुकुमत की ये अनूठी कोशिश निश्चित रूप से भाषाई प्रचार-प्रसार के लिए बेहतरीन कदम के अलावा गांव असंख्य रचनात्मक-सृजनकर्ताओं को खुद की खोज करवाने और आत्म-साक्षात्कार भी करवाएगा। प्रत्येक लेखक-साहित्यकार की चाहत होती है कि लेखनी के दौरान उन्हें प्रकृति का सानिध्य मिले, जो उन्हें स्वतंत्र और सृजनात्मक आजादी का भाव कराए। लेखक गांव को बसाने का दरअसल मकसद ही यही है कि जहां देश-दुनिया के विद्वान, विलक्षण प्रतिभाएं अपना ठिकाना बना सकें। रचनात्मक लेखनी अब महानगरों के कानफोड़ू शोरगुल और बढ़ते प्रदूषण में संभव नहीं? लेखक का मन सदैव एकांत ठौर खोजता है, लेखकों का मन बंजारा होता है जिसकी भरपाई ये गांव करेगा। उपयुक्त सुविधाओं की बात करें, तो गांव में ध्यान केंद्र, डिस्कशन सेंटर, गंगा-जमनी तहजीब वाला म्यूजियम, तीर्थटन वाटिका के अलावा पांजीटिव ऊर्जा देने वाले सैकड़ों दुर्लभ पौधे भी लगाए गए हैं। प्रत्येक पौधे के पास उसका नाम और एक स्कैनर लगाया गया है जिसे स्कैन करते ही पौधे की खासियत मोबाइल में उपलब्ध होगी। पूरी तरह डिजीटल और आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। गांव के 5 एकड़ क्षेत्रफल में शोध-अनुसंधान केंद्र भी बनाया है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। लेखक-साहित्यकार चाहे देश के हों, या विदेश के, सभी लेखक गांव में आकर एक ही स्थान पर प्रकृति, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान से नजदीक से साक्षात्कार कर विविध विषयों पर मनन-चिंतन के लिए नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। वैसे, ये परियोजना पूर्व कुलकर्मिव व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से ही शुरू हुई है। वह हमेशा से चाहते थे कि लेखनी को पलने और बढ़ने का माहौल मिलना चाहिए, जिसे सिर्फ उत्तराखंड ही पूरा कर सकता है। आज उनका अधूरा सपना भी पूरा हुआ है। गांव का उद्घाटन पिछले ही दिनों हुआ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, आध्यात्मिक विचारक स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज समेत कई वीवीआईपी ने 'लेखक गांव' का उद्घाटन किया। गांव के नजदीक हवाई पट्टी की सुविधा के संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में ये गांव ऐसा होगा, जहां हर कोई पहुंचकर दीदार करना चाहेगा। जब से गांव चर्चाओं में आया है हर कोई गांव पहुंचकर जी भरकर देखना चाहता है। आने वाले वक्त में लेखकों को पहला ठिकाना 'लेखक गांव' बनेगा, ये तय है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

समत्वं योग उच्यते

संकलित

दर्शन

जिस मनुष्य का जीवन योगयुक्त है, उसे जीवन चलाने के कर्म बंधन में बांधने वाले नहीं होते। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कमल ही रहता है। युक्त और अयुक्त का अर्थ योगयुक्त और योगअयुक्त से है अर्थात योग है समत्व बुद्धि। 'समत्वं योग उच्यते'। समत्व बुद्धि से तात्पर्य सोच-विचार कर किए गए कर्म को योगयुक्त कर्म कहते हैं। समत्व बुद्धि से अर्थ सुख-दुख, विजय-पराजय, हर्ष-शोक, मान-अपमान इत्यादि द्वंद्वों में विचलित हुए बिना एक समान शांत चित्त रहे- वही कर्मयोगी कहलाता है। स्थितप्रज्ञ : जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ, जैसे जहाज को चलाने वाले के पास ठीक दिशा बताने वाला कम्पास या यंत्र होना चाहिए, उसी तरह श्रेष्ठ जीवन जीने के तथा मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति के पास 'योग' होना चाहिए। योग नहीं तो जीवन दिशाहीन है। यही बात कृष्ण ने गीता में स्थितप्रज्ञ के विषय में कही है। बुद्धि को निर्मल और तीव्र करने के लिए योग ही एक मात्र साधन है। योग स्थित व्यक्ति साधारण मनुष्यों से विलक्षण देखने लगता है। जिस व्यक्ति के भीतर जीवन में सत्य की किरणें फैल जाती हैं, सत्य का सूर्य जगता है और जिसकी आंतरिक चेतना जागृति को, पूर्ण जागृति को उपलब्ध हो जाती है, उसका जीवन स्फोटनियस हो जाता है, सहज हो जाता है, सहज-स्फूर्त हो जाता है। उसके जीवन में किसी ढांचे को खोजना मुश्किल है। उसके जीवन में कोई बंधी-बंधाई रेखाएं नहीं होतीं।

सुख शांति चाहते हैं तो काम हमेशा ईमानदारी से करें

संकलित

प्रेरणा

एक दिन गुरु नानक के पास एक गांव का जमींदार आया। जमींदार गुरु नानक के लिए भोजन लेकर आया था। गुरु नानक ने जमींदार से कहा कि भोजन वहां रख दीजिए। जमींदार बोला कि मैं आपको खाना परोसना चाहता हूं। कृपया आप खाना खा लीजिए। नानक जी ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। तभी वहां एक गरीब व्यक्ति आया। उसने गुरु नानक से कहा कि मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूं। जमींदार ने उसकी ओर देखकर कहा कि खाना तो आ चुका है, तुम ये रोटी वापस ले जाओ। नानक जी ने कहा कि नहीं, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। जमींदार ने कहा कि मैं भी आपके लिए खाने की बहुत सी चीजें लेकर आया हूं। मेरी थाली में रोटी के साथ ही अन्य पकवान भी हैं, मिठाई भी है। नानक जी बोले कि हम उसे भी चख लेंगे। गुरु नानक ने उस गरीब की आधी रोटी खा ली और आधी अपने हाथ में रख ली। ये देखकर जमींदार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आपने ये क्या किया? मेरे स्वादिष्ट भोजन छोड़कर इसकी साधारण रोटी खा ली। नानक जी ने गरीब की आधी रोटी को हाथों से मसला तो उसमें से दूध की बूंद गिरीं। इसके बाद नानक जी ने जमींदार की मिठाई को मसला तो उसमें खून की बूंद गिरीं। वहां मौजूद लोग ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। नानक जी ने उस जमींदार से कहा कि इसकी सूखी रोटी में ईमानदारी है और तुम्हारी मिठाई में कहीं न कहीं बेईमानी है। इसलिए मैंने इस गरीब की रोटी खाई है और तुम्हारी मिठाई नहीं खाई।

अंतर्मन

आज की पाती

प्रकाश की ओर ले जाती हैं गुरु नानक जी की शिक्षाएं

हमारे देश को पावन धरा गुरुओं की कही है। इन्होंने मानव को ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया को नेक रास्ते पर ले जाने की शिक्षाएं दीं हैं। सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी ने सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधने के लिए शिक्षाएं दीं थीं। इन्होंने इक्कीसवीं सदी की समस्याओं को सदियों पहले ही भांप लिया था। गुरु नानक देव जी की जयंती देश-विदेश में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने सभी धर्मों, जातियों व वर्गों को एक समान समझने की शिक्षा दी थी। 'अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे।।' गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मात्र सिख धर्म के लिए ही आदर्श नहीं, बल्कि हर धर्म के लिए हैं। - प्रभात पाठक, दुर्ग

ट्रेंड

आदिवासी कल्याण प्राथमिकता रही

आदिवासी कल्याण हमेशा से भाजपा-एनडीए सरकार की प्राथमिकता रही है। मुझे संतोष है कि आदिवासी विकसे के तेज विकास का लाभ मेरे आदिवासी परिवारजनों को भी मिला है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

दोषियों पर कार्रवाई हो

गौतम बुद्ध नगर के थाना सीरसापुर में दोनों द्वारा दलित परिवार के साथ की गिरी में एक की मौत व कई लोगों के घायल होने की घटना अति-दुःखद एवं निन्दनीय। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को करार दे।

-मायावती, पूर्व सीएम, उप

अग्निवीरों की जीत होगी

भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही अब अग्नीवीर लाने रिटायर्ड टी टी थे जो पीछे से टरी पर उठाया खतड़ बीच में आ जाय है, इसीलिए वो आगे तीन ही मान रही है। अग्निवीरों की जीत होगी। सरकार इन्हें सुनिश्चित नहीं पाएगा सरकारी।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

बच्चा बनना पड़ता है

मातृ ने बाल दिवसे बनाने से सतरुपा याद है कि हम बच्चों के लिए दिवस बनाते सतरुपा अवलम्बन वयस्का हो जाते हैं, जब आप बच्चों की दिवस बनते हैं तो आपको बच्चा बनना पड़ता है, जैसा मैंने स्प्लिटर इंडिया बनाते सतरुपा किया था

-शेखर कपूर, निर्देशक

करंट अफेयर

उ. कोरिया ने विस्फोटक ड्रोन का परीक्षण किया

उत्तर कोरिया ने लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने के लिए डिजाइन किए गए विस्फोटक ड्रोन का परीक्षण किया है, वहीं नेता किम जोंग उन ने इन हथियारों के बड़े पैमाने पर निर्माण में तेजी लाने का आह्वान किया है। यह जानकारी शुक्रवार को सरकारी मीडिया ने दी। देश ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया है जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान निकटवर्ती अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में उन्नत लड़ाकू जेट विमानों और एक अमेरिकी विमानवाहक पोत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने कुछ तस्वीरें प्रकाशित कीं जिनमें किम कम से कम दो अलग-अलग तरह के मानवरहित हवाई वाहनों के पास अधिकारियों से बात करते नजर आ रहे हैं। इनमें 'एयस'-आकार की पूंछ और पंख वाले यान शामिल हैं जो उन ड्रोन की तरह प्रतीत होते हैं जिनका देश ने अगस्त में उस समय खुलासा किया था जब किम ने विस्फोट करने वाले ड्रोन के एक और प्रदर्शन का निरीक्षण किया था। केसीएनए ने बताया कि ड्रोन ने विभिन्न मार्गों से उड़ान भरी और लक्ष्यों पर सटीक प्रहार किया। इसके चित्रों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ड्रोन से बीएमडब्ल्यू सेडान और टैंकों के पुराने मॉडल को निशाना बनाया गया।

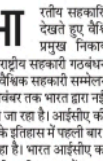

ऑफ बीट

दुनिया की आधी बड़ी झीलों में हो रहा पानी कम

दुनिया में 50 प्रतिशत से अधिक बड़ी झीलों में पानी की कमी हो रही है और इसकी प्रमुख वजहों में गर्म जलवायु और मानव उपभोग प्रमुख हैं। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के फंगचैंग याओ हैं। याओ ने कहा कि यह अध्ययन उपग्रहों और 'मॉडल' की एक श्रृंखला के आधार पर दुनिया भर की झीलों में जल भंडारण में परिवर्तन के रुझानों पर पहला व्यापक आकलन है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर के सूखने जैसे पर्यावरणीय संकट के सामने आने के बाद याओ और उनके सहयोगियों ने यह अध्ययन किया। उनके सहयोगियों में अमेरिका के कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय और कैसास विश्वविद्यालय के अलावा फ्रांस और सऊदी अरब के अध्ययनकर्ता भी शामिल थे। अध्ययन दल ने दुनिया की करीब 2000 सबसे बड़ी झीलों तथा जलाशयों के जलस्तर में हुए बदलाव पर गौर किया। पृथ्वी पर कुल झीलें जल भंडारण का 95 प्रतिशत हिस्सा हैं। अध्ययन दल ने 1992 से 2020 के बीच उपग्रहों द्वारा ली गयी करीब ढाई लाख तस्वीरों का उपयोग किया और इस तरीके से दल ने सबसे बड़ी झीलों में से 1,972 जलाशयों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। याओ ने कहा कि इस अध्ययन का निष्कर्ष चौंकाने वाला था और विश्व स्तर पर 53 प्रतिशत झीलों के जल भंडारण में कमी दर्ज की गई।

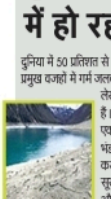

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 16 नवम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

आपसी समन्वय जरूरी

मणिपुर में नये सिरे से हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने उग्रवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस क्रम में पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त 20 कंपनियों को हवाई मार्ग से भेजा गया। इसके बाद बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय इस नतीजे पर पहुंचा कि मणिपुर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। हिंसा और अराजकता पर नियंत्रण के लिए पांच जिलों के छह पुलिस थानों को अशांत घोषित करते हुए फिर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) लागू कर दिया गया। पिछले वर्ष अप्रैल-मई में राज्य में हिंसा शुरू होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सात जिलों के 19 पुलिस थानों से अफस्पा हटा लिया था। जिन थानों में फिर से अफस्पा लागू किया गया है, उनमें इम्फाल पश्चिम जिले में सेकमाई और लमसांग, इम्फाल पूर्वी जिले में लमलाई, जिरीबाग जिले में जिरीबाग, कांगमोकपी में लीमाखोंग और विष्णुपुर में मोइरांग शामिल हैं। अफस्पा अशांत क्षेत्रों तैनात सुरक्षा बलों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार और संरक्षण देता है। अफस्पा की वापसी से जाहिर होता है कि डेढ़ साल से ज्यादा समय से जातीय हिंसा से ग्रसित मणिपुर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सोमवार को जिरीबाग में उग्रवादियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच गोलीबारी में 20 उग्रवादी मारे गए थे। इस घटना का विशेष महत्त्व इसलिए है कि पहली बार उग्रवादियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच गोलीबारी और मुठभेड़ हुई। अब तक राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बहुत संयम से काम लिया है। वास्तव में उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की एक पोस्ट पर हमला किया था। इस मुठभेड़ के बाद उम्मीद थी कि उग्रवादियों के हौसले पस्त हो जाएंगे लेकिन हिंसा और बढ़ गई। जातीय हिंसा के दौर में केंद्रीय सुरक्षा बलों को असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मैतेई समुदाय असम राइफल्स पर कुकी के प्रति पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगा रहा है तो कुकी दूसरे सुरक्षा बल पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा पर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए एकीकृत कमान को लेकर भी खींचतान है। इसके कारण मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच ठीक तरह से समन्वय नहीं हो पा रहा है। राज्य में शांति बहाली न होने की एक बड़ी वजह यह हो सकती है। मणिपुर सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल करने के उपायों पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर रही होगी।

शिक्षा में अड़ंगे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमफिल या पीएचडी डिग्री कोर्सेज को ओपन या डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत 18 कोर्सेज को भी ओपन डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड से चलाने पर रोक लगा दी है। फीजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, कानून, कृषि, हॉर्टिकल्चर, होटल प्रबंधन, कैटरिंग, पाक विज्ञान, दृश्य कला, योगा जैसे कोर्स अब ऑनलाइन या डिस्टेंस से नहीं चलाए जा सकेंगे। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या मास्टर ऑफ फिलॉसफी उन्नत शोध डिग्री योग्यता हैं। उच्चतम शिक्षा पाने वाले चुनिंदा छात्र ही इन अति विशिष्ट कोर्स तक पहुंचते हैं। सरकार ने दूरदराज या अन्य क्षेत्रों में व्यस्त छात्रों के लिए घर से बैठ कर ये शिक्षा लेने की व्यवस्था की थी। मगर विश्वविद्यालयों की धांधली या निरंतर मिलने वाली शिकायतों के चलते यूजीसी को सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रति वर्ष तमाम विश्वविद्यालयों को प्रतिबंधित करने या पाबंदियां लगाने संबंधी नोटिस जारी करता रहता है। कहना गलत नहीं है कि कुछ जरूरतमंद और उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने को इच्छुक छात्रों को इससे असुविधा भी हो सकती है। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के ढेरों विद्यार्थी हैं, जो कोई रोजगार या नौकरी करते हुए अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिहाज से ओपन या ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने को मजबूर होते हैं। ऐसे जरूरतमंदों के लिए भी आयोग को रास्ता सुझाना चाहिए। आयोग का काम मान्यता की जांच करने की सलाह पर ही खत्म नहीं हो जाता। उसे सख्तीपूर्वक ऐसे किसी भी विश्वविद्याल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल छात्रों का भविष्य चौपट होता है। बल्कि उनका बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। विज्ञापनों द्वारा ऐसे संस्थान जब प्रचार कर रहे होते हैं, उसी वक्त इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे, दुनिया जब तकनीक और संचार व्यवस्था द्वारा शिक्षा को सुविधाजनक बना रही है, ऐसे में विवि की लापरवाही का खमियाजा छात्रों को भुगतने से बचाना भी आयोग का ही जिम्मा है।

कटाक्ष/ कबीरदास

हाय बुलडोजर: शोक पत्री

हम भगवाइयों के प्रिय बुलडोजर भैया नहीं रहे। 12 नवम्बर को हृदयाघात से उनका असमय निधन हो गया। खासे तंदुरुस्त थे। पलक झपकते ही, मजबूत से मजबूत इमारतों को धूल चटा देते थे। पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। सबसे ऊंची अदालत की फटकार से दिल का जबर्दस्त दौरा पड़ गया। वकीलों की सारी कोशिशों के बावजूद, बड़े भैया को बचाया नहीं जा सका। उठावनी, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद होगी।

बुलडोजर भैया पर योगी जी का विशेष स्नेह था। वैसे, भैया प्रिय तो सभी भगवा मुख्यमंत्रियों के थे। सिर्फ मुख्यमंत्रियों के ही नहीं, नीचे वालों के भी। जिलाधीशों के भी, नगर पालिका प्रमुखों के भी। सच पूछिए तो सभी भगवाइयों के और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी। सुना नहीं कैसे अमेरिका के एक शहर में तो भगवाई पंद्रह अगस्त के जुलूस में बुलडोजर ही ले आए थे। पर अमेरिका वालों के अजब-गजब कानून, जुलूस में बुलडोजर लेकर निकलने पर शहर की सरकार ने भाइयों पर जुर्माना ही ठोक दिया। खैर! इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री को तो बुलडोजर इतना पसंद आया कि गुजरात में बुलडोजर की फैक्टरी के दौरे पर, भाई बुलडोजर पर सवारी करने ही निकल पड़े। यह दूसरी बात है कि बुलडोजर की तरह, अगले की प्रधानमंत्री की कुर्सी की उम्र भी काफी कम निकली। फिर भी योगी जी जितना प्रेम बुलडोजर को और किसी ने नहीं दिया होगा। उनके स्वागत में बुलडोजर आने लगे। उनके जुलूसों में बुलडोजर अपने करतब दिखाने लगे। और तो और योगी जी ने अपना नाम ही बदल कर बुलडोजर बाबा रख लिया। भ्रम फैलाते हैं वो लोग जो कहते हैं कि योगी जी को उतना ही प्रेम एन्काउंटर से भी है। बेशक, एन्काउंटर से प्रेम है, मगर उतना नहीं। वरना नाम बदल कर क्या एन्काउंटर बाबा नहीं रखते? बुलडोजर भैया को गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के घरों-दूकानों पर तांडव करने में बहुत मजा आता था। अब वैसा तांडव कैसे होगा? डर-डर के, अदालत की शर्तें देख-देख कर अब क्या तांडव होगा? तांडव की हमारी धार्मिक परंपरा खतरे में है। हाय भैया तुम तो बीच में ही छोड़ कर चले गए। हिन्दू राष्ट्र छोड़ो, 'एक देश एक चुनाव' तक का इंतजार नहीं किया। हाय, बुलडोजर भैया हाय!

द्रविड़ राष्ट्रवाद रहेगा या ढहेगा

थलापति विजय की पार्टी

मुकेश बालयोगी

तमिल अभिनेता थलापति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर प्रदेश की राजनीति के दोनों ध्रुवों-द्रमुक और भाजपा-को चौंका दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से डेढ़ साल पहले विजय की इस मुनादी ने सियासतदानों के साथ ही तमिलनाडु के सियासी पंडितों को भी सकते में डाल दिया है। पहली ही रैली में तीन लाख लोगों को जुटाने में कामयाब हुए विजय ने साबित कर दिया है कि सिनेमा के पर्दे ही नहीं, सियासत के मंच पर भी उनका जादू सिर चढ़कर बोलने वाला है। तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति की लीक से इतर उनकी पार्टी तमिलगा वेन्नी कझगम (टीवीके) ने द्रविड़ राष्ट्रवाद के उन्मादी घोड़े पर सवारी करने से परहेज किया है। हालांकि विजय इसका मुखर विरोध करते भी नहीं दिख रहे हैं।

विजय की कोशिश तमिलनाडु में वैकल्पिक राजनीति देने की है। इसलिए सामाजिक न्याय के नारे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्मिता की भावनाओं को भुनाने के लिए उसे उछालने से भी परहेज नहीं कर रहे। लेकिन उनकी शब्दावली में द्रविड़ अस्मिता की जगह तमिल अस्मिता को तवज्जो है। जाहिर है कि वे ऐसा कर हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बच रहे हैं क्योंकि द्रविड़ अस्मिता और तमिल अस्मिता में महीन सी विभाजन रेखा है। द्रविड़ अस्मिता जहां हिन्दू शास्त्रों, परंपराओं और मान्यताओं को खारिज करती है, वहीं तमिल अस्मिता हिन्दू परंपरा के तमिल ऋषियों, विद्वानों और शास्त्रों की महिमा के गर्व पर केंद्रित है। इससे विजय ने तमिलनाडु की राजनीति की दोनों प्रमुख धाराओं को साथ साधने की कोशिश की है। इस राजनीति से द्रविड़वादी और हिन्दुत्व की राजनीति के पैरोकार, दोनों के समर्थकों के बड़े हिस्से का रुझान टीवीके की ओर हो सकता है। परंतु इस राह में एक खतरा भी है। तमिलनाडु में राजनीति को लेकर जनमानस तक में जिस तरह की तीखी वैचारिक विभाजन देखने को मिलती है, उस स्थिति में मध्यमार्गी या उदारपंथी राजनीति को तवज्जो मिलने की संभावना कम ही दिखती है। विजय द्रविड़ राजनीति से अलग तमिल अस्मिता की जो लाइन ले रहे हैं, उसके तहत भाजपा भी उनके निशाने पर है, परंतु इसके लिए वे हिन्दुत्व पर करुणानिधि या स्टालिन की तरह प्रहार भी नहीं कर रहे। यह उनके सोचे-समझे वैचारिक अभियान का हिस्सा है। इसके तहत वे जहां हर विचारधारा के मोहभंग समर्थकों में सियासी आधार तलाश रहे हैं, वहीं तमिल राजनीति में हाशिये पर रही मध्यमार्गी राजनीति को मुख्य आधार देने की कोशिश भी कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के नारे को उछाल कर उन्होंने अपने दूरगामी राजनीतिक इरादे के भी संकेत दे दिए हैं। इसके तहत सियासी रसूख में हाशिये पर रहीं जातियों को एकजुट कर बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में विकसित करने का प्रयोग भी शामिल हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में भाजपा इसका सफल प्रयोग कर चुके हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मण विरोध पर केंद्रित द्रविड़ अस्मिता की राजनीति ही ज्यादा प्रभावी रही है। तमिलनाडु में पिछड़े या दलितों के अंदर जातीय अस्मिता की राजनीति अभी गौण है। देश भर में जातीय राजनीति के उभार, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में जातीय गणित के मुताबिक हिस्सेदारी की मांग जोर पकड़ रही है। तमिलनाडु भी इससे अछूता नहीं रह सकता। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो 'जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी' के नारे का स्पेस तमिलनाडु की राजनीति में काफी हद तक खाली है। विजय के लिए इस अवसर को भरने के पर्याप्त अवसर हैं। वह जिस तमिल अस्मिता के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं, उसकी जड़ें सुदूर अतीत में कहीं न कहीं हिन्दू या सनातन परंपरा से जाकर एकाकार होने लगती हैं।

भाजपा को भी प्रखर राष्ट्रवाद या व्यापक हिन्दुत्व के आवरण में एक बड़ी विचारधारा के घटक के तौर पर इससे परहेज नहीं है। इसलिए तमिलनाडु में पैर जमाने के लिए भाजपा इसे प्रोत्साहित भी करती रही है। तमिलनाडु में भाजपा के सैद्धांतिक रणनीतिकार द्रविड़ राष्ट्रवाद के खिलाफ तमिल उपराष्ट्रवाद को आजमाते भी रहे हैं। तमिलनाडु में भाजपा की सियासी सफलता के सतत परंतु सीमित विस्तार में इसकी काफी भूमिका मानी जाती रही है। अन्ना द्रमुक के साथ भाजपा की गठबंधन साझेदारी के भी संभव हो सकने के पीछे यह एक बड़ा कारण रहा। द्रमुक और स्टालिन की काट में भाजपा इसी का प्रयोग करती दिख रही है।

ऐसे में देखा जाए तो थलापति विजय और भाजपा की राजनीति का वैचारिक आधार कई बिंदुओं पर काफी हद तक मिलता-जुलता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि विजय तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सियासत को वैचारिक विस्तार देंगे या समान धरातल पर वोटों के साझीदार की भूमिका निभाएंगे। यह साझेदारी समान आधार पर नये वोट बैंक पैदा कर तीसरा विकल्प देने की कोशिश, व्यापक वातावरण बना कर भाजपा को ताकतवर बनाने और उसी समर्थन से नई राजनीतिक शक्ति बनने की भी हो सकती है। या फिर समान आधार पर भाजपा के साथ वोटों के बंटवारे से द्रमुक को फायदा पहुंचाने की हद तक भी जा सकती है। विजय के सियासी उभार से भाजपा ही डरी हुई नहीं है। द्रमुक नेताओं की चिंता भी साफ देखी जा रही है क्योंकि विजय की तमिल अस्मिता के मुद्दे में सनातन धर्म के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक आयाम के अलावा वे सभी मुद्दे शामिल हैं, जिनकी बात द्रमुक नेता करते रहे हैं। इसलिए द्रविड़ विचारधारा के समर्थकों के एक बड़े हिस्से की स्वीकार्यता भी विजय को मिल सकती है।

इन्हीं मुद्दों को बिना हिन्दुत्व विरोध के उदार तरीके से पेश करने के कारण भाजपा के साथ टीवीके का समझौता हो गया तो द्रमुक को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिणी राज्यों में अपनी सीमा के अहसास के कारण भाजपा को इससे परहेज भी नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश में भी भाजपा ने अपने गठबंधन साझीदार पवन कल्याण को मुखर हिन्दुत्व का पैरोकार बनने के लिए पूरा समर्थन दिया है, बल्कि प्रेक्षकों का तो यहां तक कहना है कि तिरुपति मंदिर में मिलावटी मिठाई का मामला सामने आने के बाद उठे विवाद में तो भाजपा पवन कल्याण के पीछे चलती नजर आई। इसलिए फिलहाल थलापति विजय के दोनों हाथ में लड्डू हैं-वे तमिलनाडु की राजनीति में नई धारा तैयार करें या फिर द्रमुक के खिलाफ भाजपा के साथ रणनीतिक मोर्चा बनाएं।

(लेख में विचार निजी हैं)

तमिलनाडु में थलापति विजय के सियासी उभार से भाजपा ही डरी हुई नहीं है। द्रमुक नेताओं की चिंता भी साफ देखी जा रही है क्योंकि विजय की तमिल अस्मिता के मुद्दे में सनातन धर्म के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक आयाम के अलावा वे सभी मुद्दे शामिल हैं, जिनकी बात द्रमुक नेता करते रहे हैं। इसलिए द्रविड़ विचारधारा के समर्थकों के एक बड़े हिस्से की स्वीकार्यता भी विजय को मिल सकती है। इन्हीं मुद्दों को बिना हिन्दुत्व विरोध के उदार तरीके से पेश करने के कारण भाजपा के साथ टीवीके का समझौता हो गया तो द्रमुक को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है

रूस के साथ व्यापार 2030 तक 100 अरब डॉलर पर पहुंचने का भरोसा

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत-रूस के बीच व्यापार में चुनौतियां रही हैं, खासकर भुगतान तथा लॉजिस्टिक्स के संबंध में...और इनसे काफी हद तक निपटा भी गया है लेकिन अब भी कुछ किया जाना बाकी है
- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर 25वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की हालिया बैठक में उन्होंने कहा, 'भारत ने रूस से उर्वरक, कच्चे तेल और कोयले की आपूर्ति पर बात की है
- इसी तरह, भारत का औषधि उद्योग रूस के लिए किफायती और विश्वसनीय स्रोत के रूप में उभरा है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

अर्वन नक्सल दरअसल, भाजपा के मन का एक डर है। इस भय की सबसे अच्छी व्याख्या हिन्दी के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ पांडेय की कविता 'उनका डर' करती है: 'वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन-दौलत, गोला-बारूद, पुलिस-फौज के बावजूद? वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे।'

योगेन्द्र यादव, नेता, कांग्रेस
@_YogendraYadav

कबूतरों से खतरा भगवती प्रसाद डोभाल

हल तो निकालना ही होगा

हाल ही में कुछ अध्ययनों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें कबूतरों से खतरे की बात बताई गई है। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के डॉ. मीत घोनिया ने बताया कि कबूतर की बीट में साल्मोनेला, ई. कोली और इंफ्लूएंजा-जैसे रोगाणु होते हैं, जिनसे अस्थमा-जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। कहा है कि इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो कबूतरों के संपर्क में रहे हैं। उसका कारण यही माना जा रहा है कि कबूतरों की बीट में जो रसायन पाया जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है।

डॉ. मीत ने बताया कि जब कबूतर एक जगह ज्यादा संख्या में होते हैं, तब उनकी बीट से क्रिप्टोकोकी जैसे फंगल बीजाणुओं के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यही बीजाणु हवा में अधिक मात्रा में होने के कारण व्यक्ति की सांस के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। फिर सांस लेने में परेशानी हो जाती है। इस परेशानी से अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा बीजाणु है, जो मनुष्य की जान लेने का कारण बनता है।

गंभीर बीमारी टीबी के फैलने के खतरों को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली में कबूतरों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कबूतरों को दाना देने वालों को रोका जाए। यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जहां-जहां दिल्ली शहर में कबूतरों को दाना डालने के स्थान लोगों ने बनाए हैं, उन्हें बंद किया जाए। एमसीडी द्वारा दाना डालने वाले स्थानों को रोकने से जनता खुश नहीं है। उसका कारण है लोगों की भावना। वे इन पक्षियों को जीवित रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दाना देने वाली जगहों पर ऐसे व्यापारी भी बैठे होते हैं, जो कबूतरों के लिए दाना बिकवाते हैं; वे भी इस रोक से परेशान हैं, उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है। दिल्ली के कनाट प्लेस, बाराखंबा, मंडी हाउस, पटेल नगर, शंकर रोड, मंदिर मार्ग, कड़कड़डूमा, करोल बाग और रोहतक रोड के कई इलाकों के चौक-चौराहों पर कबूतरों के लिए दानागाह हैं। इन स्थानों पर नागरिक दूर-दूर से कबूतरों को दाना देने आते हैं, और उनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त भी किया जाता है। देखा गया है कि अधिकांश पक्षियों की प्रजातियां दिल्ली से लुप्त होती जा रही हैं।

गौरया को दिल्ली राज्य के पक्षी की मान्यता दी गई थी पर आज वह खोजने पर भी नहीं मिलती; लुप्त होने का कारण दिल्ली अब उसके रहने लायक नहीं रह गई। छोटे-छोटे स्थानों और पार्कों में वह अपनी संतति बढ़ाने के लिए घोसलों का निर्माण करती थी, लेकिन अब वे स्थान उसके लिए उपयुक्त नहीं रहे। साथ ही, भीड़ भरे स्थानों में गौरया का जीना दूभर हो गया है। ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियां दिल्ली से लुप्त हो गई हैं। अब कबूतर ही दिल्ली में सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वे बड़ी-बड़ी बहुमंजिली इमारतों में अपने घोसले बनाने का प्रयास करते हैं, छिपने का स्थान ढूंढ़ कर संतति बढ़ाते हैं। इसलिए कुछ स्थानों को छोड़ कर कबूतर दिख जाते हैं। वैसे कबूतर का मनुष्य से पुराना रिश्ता भी है। पुराने जमाने में वे ही संदेशवाहक का काम करते थे। राजा-महाराजाओं के संदेशों को पहुंचाने का इतिहास कबूतरों का ही रहा है।

इससे पता चलता है कि वे अक्सर आदमियों के करीब ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज देश की बढ़ती आबादी महानगरों में ही सिमटने को अपना भविष्य मानती है। इस कारण इको सिस्टम ही बदल रहा है। वैज्ञानिक उपलब्धि का फायदा मनुष्य तो ले रहा है पर पर्यावरण को दरकिनार कर नई-नई दुश्वारियों को बुलावा भी दे रहा है। संतुलित विकास का समीकरण ही बदल गया है। इसके साथ ही नये-नये वायरस भी जन्म ले रहे हैं, उनकी वजह से पूरा विश्व ही परेशानियों से जूझ रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोरोना काल है। मृत्यु का तांडव कोरोना काल में रहा। अब आप अपने आसपास के जीव-जंतुओं को ही मिटाना चाहते हैं। वैसे, शांति के प्रतीक कबूतरों से अगर वाकई मानव जीवन को खतरा है, तो इसका हल तलाशना भी वैज्ञानिकों के लिए जरूरी है।

दिल्ली के चिकित्सकों ने भी कबूतरों के आवासों को मिटाने के लिए एमसीडी की योजना को सही माना है, और कबूतरों के पोषण के स्थानों को मिटाने का बिल लाया जा रहा है, लेकिन कबूतरों को संरक्षण देने में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 काम कर सकती है। दिल्ली के प्रशासकों और वैज्ञानिकों को ऐसे अनुसंधान की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें फंगस, साल्मोनेला ई. कोली-जो कबूतरों को हमसे दूर करता जा रहा है-को मारने के लिए दवा का ईजाद किया जाना निहायत जरूरी है, ताकि हमारा एक प्रिय पक्षी हमसे दूर न होने पाए।

अंतर्मुख संत राजिन्दर

ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होने का अर्थ है, आत्मिक आनन्द की अवस्था में होना। तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है। अंर्तमुख होने से हम उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं जो समस्त ज्ञान का भण्डार है। ध्यान-अभ्यास द्वारा हम मृत्यु के द्वार को लांघ कर, उस आनन्द और सौंदर्य को पा लेते हैं, जो हमारे भीतर हमारा इंतजार कर रहा है। उस अवस्था को पाकर हमें मृत्यु की तलवार का डर नहीं सताता क्योंकि हम जीते-जी उस स्थान को देख लेते हैं, जहां मृत्यु के बाद हमें जाना है। तब हमें ईसा मसीह के इस वचन का सही अर्थ मालूम होता है, 'हां, मैं मृत्यु की वादी में चहलकदमी करता हूं परन्तु मैं भयभीत नहीं हूं क्योंकि तुम मेरे साथ हो'। संतों-महात्माओं, जिन्होंने पारलौकिक जीवन को देखा है, ने भी अपनी वाणी में मृत्यु के बारे में वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यह ऐसा कुछ नहीं जिससे कि हम भयभीत हों बल्कि उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है-जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द, मरने ही ते पाइये पूरन परमानन्द। सेंट टेरेसा ने कहा है, 'मैं नहीं मरती, मैं तो जीवन में प्रवेश करती हूं'। इस धरती, जिसे हम जीवन कहते हैं, पर जागृत महापुरुषों के लिए यह एक निद्रा है; मृत्यु द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करना ही, जागना है। सेंट पॉल ने कहा है, 'ओ मृत्यु! तुम्हारा देश कहां है? ए कब्र! तुम्हारी जीत कहां है'? हम जीते-जी इसी जीवन में उस जगह को देख सकते हैं, जो इस जीवन के बाद हमारे लिए तैयार की गई है। अंतर में प्रवेश करके जब हम यह अनुभव पा लेते हैं, तो आत्मा का अजर-अमरता होना हमारे लिए कोई सुनी-सुनाई बात नहीं रह जाती, बल्कि एक ठोस विश्वास, एक अनुभूति बन जाती है। अनेक तरह के डर ऐसे होते हैं, जिनके पीछे कुछ खोने का, दुःख का या मृत्यु का डर होता है। एक बार आत्मा के अमर होने का अनुभव होने के बाद हमारा भय समाप्त होने लगता है। प्रभु से एकता की अवस्था में हमारी आत्मा किसी भय को नहीं जानती। उस एकता के ज्ञान का अभाव ही, भय का कारण होता है। वास्तव में सच्चाई से दूर होना ही पाप है।

रीडर्स मेल

सुप्रीम कोर्ट का सही निर्णय

भारतीयों के लिए पक्का घर सपना सरीखा है। ऐसे में किसी का आशियाना बिना नोटिस और स्पष्ट कारण के बिना ध्वस्त करना न केवल उनके सपनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है, बल्कि असंवैधानिक भी है। घर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का होता है जो कई लोगों की मेहनत, आशा और भावनाओं का केंद्र होता है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे परिवार को देना न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब बिना 15 दिन पूर्व नोटिस के किसी भी निजी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि सार्वजनिक संपत्ति पर आतिक्रमण और अवैध कब्जे पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। केवल अवैध निर्माण ही तोड़ जा सकता है, वह भी 15 दिन के पूर्व नोटिस के साथ। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाएगा और जनता के अधिकारों की रक्षा होगी।

बिनीत रॉय, नवादा, बिहार

राजनीतिक दलों के बेतुके तर्क

शीर्ष न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को आरक्षण में उपवर्गीकरण के जो दिशा-निर्देश दिए गए थे, उन्हें लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। उपवर्गीकरण आरक्षण पर राजनीतिक दलों द्वारा बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। इन दलों द्वारा आरक्षित वर्गों के लोगों को प्रदर्शन के लिए भी उकसाया जा रहा है। यह एक घटिया राजनीति है। इसके विरोध में जो लोग खड़े हैं, वे वही हैं, जिन्होंने आरक्षण की मलाई का सबसे अधिक मजा चखा है, और चख रहे हैं। संविधान में जिन वंचितों और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उद्धार के लिए आरक्षण का प्रवधान रखा गया था, वह उद्देश्य स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। उपवर्गीकरण के विरोधियों का कहना है कि इससे वर्गीय एकता को ठेस पहुंचेगी और वर्ग के अंदर ही द्वेष की भावना पनपेगी। इस पर यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि जब जाति के नाम पर आरक्षण का निर्धारण किया गया था तो तब यह आशंका क्यों नहीं उठाई गई कि जातिगत आरक्षण से विभिन्न जातियों के बीच द्वेषभाव पनपने के साथ-साथ धार्मिक एकता को भी ठेस पहुंचेगी।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

सादगीपूर्ण हों शादी समारोह

अब विवाह महज एक वृहद् आयोजन या उत्सव बन कर रह गया है। ऐसे में नवधनाढ्य वर्ग दिखावे के लिए खूब खर्च करता है। विवाह समारोह में दिखावे की बढ़ती प्रवृत्ति निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों को कर्जदार बना रही है। यह स्थिति चिंताजनक है। व्यक्तिगत और संस्थागत रोक-टोक के अभाव में विवाह आयोजनों में आजकल खर्च ज्यादा किया जा रहा है। लोग अपनी झूठी शान और दिखावा करने के लिए शादियों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। महंगे कपड़ों, महंगी गाड़ियों, मैरिज गार्डन, डीजे पार्टियों और शराब के साथ आलीशान शादी का दिखावा करते हैं। सादगी के साथ भी आकर्षक विवाह समारोह का आयोजन किया जा सकता है। महंगे आभूषण, आतिशबाजी, महंगी साज-सज्जा, मेहमानों की अधिकता और दिखावे के विवाह आयोजनों से फिजूलखर्ची स्वाभाविक है। दिखावारहित विवाह आयोजनों को प्राथमिकता देकर फिजूलखर्ची से बचा जा सकता है।

गोपाल सोनी, धार, मप्र
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

बुलडोजर पर लगाम

अदालत का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर न्याय की प्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि अवैध विध्वंस में शामिल अधिकारियों को अब संपत्ति बहाल करने और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह निर्णय दंडात्मक उपायों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मनमाने विध्वंस पर बढ़ती चिंता का जवाब है, जो अक्सर अपराध के आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाते हैं। निर्णय सख्त प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है और अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही को लागू करता है। इस दायित्व में ध्वस्त संपत्तियों को बहाल करने और प्रभावित पक्षों को मुआवजा देने की लागत को कवर करना शामिल है। यह उपाय अधिकारियों को उचित प्रक्रिया की अवहेलना करने से रोकने के लिए बनाया गया है और राज्य की शक्ति का प्रयोग करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने ढंग से विध्वंस को रोकने के लिए अनिवार्य प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं- व्यक्तिगत सुनवाई के साथ-साथ 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक है; एक विस्तृत अंतिम आदेश यह बताते हुए दिया जाना चाहिए कि विध्वंस ही एकमात्र व्यवहार्य कार्रवाई क्यों है और अंतिम आदेश के बाद 15 दिन की छूट अवधि प्रभावित पक्ष को कानूनी सहारा लेने या परिसर खाली करने की अनुमति देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने कार्यों को रोकने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी विध्वंस नोटिस और आदेशों के लिए एक डिजिटल पोर्टल पर वास्तविक समय में अपडेट अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पूरी विध्वंस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, जिसमें जवाबदेही और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए शामिल अधिकारियों की सूची होनी चाहिए। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अवमानना कार्यवाही और अभियोजन का जोखिम है, जो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

यह निर्णय भारत में शासन, कानून के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए दूरगामी निहितार्थ रखता है। दंड के रूप में किए गए विध्वंस को प्रतिबंधित करके, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कानूनी सिद्धांत को पुष्ट किया है कि कार्यपालिका न्यायाधीश और प्रवर्तक के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। यह निर्णय मनमाने राज्य की कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, यह पुष्टि करता है कि दंडात्मक उपायों का सामना करने से पहले हर किसी को उचित प्रक्रिया का अधिकार है। यह निर्णय प्रशंसनीय है क्योंकि यह मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस पर रोक है, जो अक्सर आश्रय के अधिकार का उल्लंघन करता है, परिवारों और समुदायों को प्रभावित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इस बात पर जोर देता है कि अपराधों के संदिग्ध व्यक्तियों को लक्षित करने वाली कार्रवाइयों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यह निर्णय उन कई परिवारों के लिए राहत की बात है जो विध्वंस से डरते हैं क्योंकि उनमें से कोई कानून के गलत पक्ष में हो सकता है। हालाँकि, यह निर्णय नौकरशाहों के राजनीतिक आकाओं पर जिम्मेदारी डालने में विफल रहा है जिनके इशारे पर अक्सर ऐसी कार्रवाई की जाती है। फिर भी, यह उन अधिकारियों पर लगाम लगाएगा जो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए हद से आगे निकल जाते हैं। यह एक साहसिक कदम है जो प्रशासनिक आचरण को नया रूप दे सकता है।

कृत्रिम बुद्धि का बढ़ता प्रभाव

जैसे-जैसे अद्वितीय सौंदर्य समाधानों की वैश्विक मांग बढ़ रही है, इस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग अनुकूलन, दक्षता और उपभोक्ता संतुष्टि की दिशा में एक गहन बदलाव को दर्शाता है।

दिनेश सूद
(लेखक, भारतीय कौशल विकास निगम से जुड़े हैं)

नई तकनीकों का उपयोग करने वाले अभिनव उत्पाद और सेवाएं सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में हलचल मचाने लगी हैं। परिणामस्वरूप, पारंपरिक कौशल को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकी कौशल जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ऐप विकास, ट्राई-ऑन सेवाओं के लिए संवर्धित वास्तविकता, डेटा एनालिटिक्स और उन्नत ग्राहक जुड़ाव रणनीतियों के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है। एआई ने सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खासकर जब अनुकूलन और वैयक्तिकरण की मांग बढ़ी है।

यह प्रवृत्ति विविध ग्राहक वरीयताओं, जीवन शैली, शरीर के प्रकार और आनुवंशिक कारकों को दर्शाती है। माइक्रोसाफ्ट टीमों के लिए मेबेलिन केएआई संचालित मेकअप फिल्टर के बारे में हाल ही में आई खबरों ने सौंदर्य क्षेत्र में एआई की भूमिका पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि एआई किस तरह से उद्योग को बदल रहा है और नवीनतम विकास पर अपडेट रहना चाहिए। 2020 में एआई का उपयोग करने वाले वैश्विक सौंदर्य उद्योग का मूल्य 216.12 मिलियन था और 2027 तक 3.26 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। एक उद्योग रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 2027 तक सौंदर्य क्षेत्र में एआई की वार्षिक वृद्धि दर 33.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

कई प्रयोगशालाओं ने एआई-संचालित त्वचा परामर्श उपकरण विकसित किए हैं जो त्वचा की उम्र बढ़ने का विश्लेषण करने के लिए संवर्धित वास्तविकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करते हैं। ये उपकरण उम्र बढ़ने के संकेतों को पहचान कर सकते हैं और त्वचा की मजबूती का आकलन कर सकते हैं, जिससे आगे की गिरावट को रोकने के लिए अनुरूप त्वचा देखभाल सिफारिशें मिल सकती हैं। उनके एल्गोरिदम 10,000 छवियों और 15 वर्षों की त्वचाविज्ञान विशेषज्ञता पर प्रशिक्षित हैं। उपयोगकर्ता एक सेल्फी ले सकते हैं और अपनी त्वचा की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए अपनी उम्र और त्वचा का प्रकार प्रदान कर सकते हैं और साथ ही एक व्यक्तिगत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्हें अनुकूलित त्वचा देखभाल नुस्खे प्राप्त होंगे। एआई त्वचा की स्थितियों का विश्लेषण करने, व्यक्तिगत त्वचा देखभाल और स्वास्थ्य दिनचर्या की सिफारिश करने और यहां तक कि रुझानों की भविष्यवाणी करने में सहायता करता है, जिससे अंततः उत्पाद विकास और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है। मुहांसे दुनिया भर में एक आम समस्या है, जो 80 प्रतिशत किशोरों और 40 प्रतिशत वयस्कों को प्रभावित करती है।

एआई के साथ, विभिन्न जातीय त्वचा प्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली 6,000 छवियों का एक डेटाबेस, मुहांसे से पीड़ित लोगों के लिए सटीक विश्लेषण और व्यक्तिगत नियमित अनुशंसाओं को सक्षम बनाता है। यह अभूतपूर्व एआई तकनीक वास्तविक त्वचा विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन की गई 10,000 प्रामाणिक छवियों की लाइब्रेरी से आकर्षित होती है, जो आठ मैदानिक मापदंडों और त्वचा के विभिन्न प्रकारों में लगभग 97 प्रतिशत की सटीकता दर प्राप्त करती है।

लगातार विकसित हो रहे सौंदर्य और कल्याण उद्योग में, जहां नवाचार आत्मविश्वास और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है, एआई पहले से कहीं अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत उत्पाद निर्माण बनाने में एक शक्तिशाली सहयोगी बन गया है। अपने विविध अनुप्रयोगों और क्षमताओं का लाभ उठाकर, एआई एक क्रांति ला रहा है जो सौंदर्य और कल्याण उत्पादों के विकास, व्यक्तिगतकरण और विपणन के तरीके को बदल रहा है। ट्रेंड स्पॉटिंग से लेकर सटीक उत्पाद निर्माण तक, एआई सौंदर्य उद्योग को रोमांचक और अभूतपूर्व तरीकों से नया रूप दे रहा है। निर्माण प्रक्रिया में एआई को एकीकृत करने से उत्पाद की प्रभावशीलता भी सुनिश्चित हो सकती है। एआई एल्गोरिदम यह अनुकरण कर सकते हैं कि त्वचा द्वारा अवयवों को कैसे अवशोषित और चयापचय किया जाता है, संभावित अवांछित अंतःक्रियाओं या दुष्प्रभावों की पहचान करते हुए।

यह दृष्टिकोण नए उत्पादों को बाजार में लाने से जुड़े जोखिमों को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता अपनी भलाई से समझौता किए बिना इष्टतम परिणाम प्राप्त करें। परंपरागत रूप से, किनकेयर उत्पादों को एक ही आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है, जो अक्सर व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की अनूठी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है। एआई त्वचा के प्रकार, आयु, पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं सहित विभिन्न डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करके इस पद्धति को बदलता है।

ड्रू-संचालित उपकरणों का उपयोग करके, ब्रांड प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किनकेयर उत्पाद बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एआई एल्गोरिदम फ़ोटो और प्रश्नावली के माध्यम से उपयोगकर्ता की त्वचा की स्थिति का आकलन कर सकते हैं, सक्रिय अवयवों की विशेष सांद्रता वाले उत्पादों की सिफारिश या निर्माण कर सकते हैं जो व्यक्तिगत त्वचा संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त, एआई आणविक संरचनाओं का विश्लेषण करके यह अनुमान लगा सकता है कि नए यौगिक मानव त्वचा के साथ कैसे बातचीत करेंगे, जिससे पारंपरिक परीक्षण-और-त्रुटि विधियों के समय और लागत में काफी कमी आएगी।

एआई सिस्टम प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री, उत्पाद और किनकेयर रूटीन की सिफारिश करता है। यह ब्रांडेड उत्पादों का सुझाव भी दे सकता है जो सौंदर्य और कल्याण उद्योग में विशिष्ट स्थितियों को संबोधित करते हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राहक की प्राथमिकताओं से गहराई से जुड़ना है। जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, यह ऐसे समाधानों का वादा करती है जो भविष्य में दिखावट और सेहत दोनों को बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका डेटा निजी रहता है; इसे संग्रहीत नहीं किया जाता है और केवल आप ही परिणाम देख सकते हैं जब तक कि आप अपनी जानकारी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चुनते। सौंदर्य और कल्याण उद्योग में सफलता के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव महत्वपूर्ण है। एआई तकनीक प्रत्येक ग्राहक की अनूठी प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, सौंदर्य कंपनियों से ऐसी अभिनव सेवाएँ शुरू करने की अपेक्षा की जाती है जो ग्राहकों के साथ संपर्क को बढ़ाएँ और सौंदर्य खाता के वैश्विक विकास में योगदान दें। इन तकनीकी प्रगति के साथ-साथ ऑनलाइन सेवाएँ तेजी से विकसित हो रही हैं। वेबसाइट, आकर्षक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और ऑनलाइन मार्केटप्लेस का महत्व बढ़ रहा है। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र में ऑनलाइन राजस्व का हिस्सा, जो 2017 में लगभग 4.6 प्रतिशत था, 2025 तक बढ़कर 18.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। सौंदर्य और कल्याण उद्योग का भविष्य एक ऐसे सर्वव्यापी अनुभव पर निर्भर करेगा जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन इंटरैक्शन को सहजता से एकीकृत करता है, उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है।

ब्यूटी रिटेल में वर्चुअल ट्राई-ऑन और परामर्श मानक बन गए हैं; हालाँकि, मानवीय कनेक्शन को दोहराना एक चुनौती बनी हुई है। ऑनलाइन प्रभावशाली व्यक्ति और मुझे दिखाओ कैसे सामग्री लोकप्रियता प्राप्त कर रही है क्योंकि उपभोक्ता उन सेवाओं में महारत हासिल करना सीख रहे हैं जो वे पहले पेशेवरों से चाहते थे।

इसके अतिरिक्त, फेसवुक लाइव और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग युवा उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण रूप से आकर्षित करती है। भारत में, सौंदर्य और कल्याण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता और आकांक्षा ने सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं पर खर्च में वृद्धि की है।

सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर प्रति व्यक्ति खर्च 2017 में 450 रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 2022 में 684 रुपये हो गया, और 2025 तक इसमें और वृद्धि होकर 772 रुपये होने का अनुमान है। आज के उपभोक्ता अद्वितीय अनुभव की मांग करते हैं, जिससे पारंपरिक दृष्टिकोण कम प्रभावी हो जाते हैं।

सुविधा और ऑन-डिमांड सेवाओं के लिए बढ़ती प्राथमिकता है, जो कामकाजी पेशेवरों के तेज़-तर्रार जीवन में आवश्यक हो गई है। नतीजतन, सौंदर्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यबल के भीतर हस्ताक्षरणीय कौशल की बढ़ती आवश्यकता है, क्योंकि ग्राहक सेवा विशेषज्ञता की मांग अधिक होती जा रही है।

अदृश्य शक्तियों का अनावरण

शक्ति के रूप प्रामाणिक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए केंद्रीय हैं। प्रकृति की ऊर्जाएं सुलभ हैं, लेकिन इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है।

अश्विनी गुरुजी
(लेखक, आध्यात्मिक गुरु हैं)

सृष्टि कुछ शक्तियों द्वारा संचालित है। जैसे-जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, आप उनके रूपों का अनुभव कर सकते हैं। 365 दिनों में से प्रत्येक दिन एक विशिष्ट शक्ति द्वारा संचालित (संचालित) होता है। इसीलिए योग में नियम और दैनिक अभ्यास के महत्व पर जोर दिया जाता है। यदि कोई एक दिन भी साधना से चूक जाता है, तो उस दिन की शक्ति पीछे रह जाती है और पूरे वर्ष की साधना व्यर्थ हो जाती है क्योंकि ब्रह्माण्ड में, यदि एक भी चीज़ छूट जाती है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है - हमारा शरीर, पृथ्वी, साथ ही अन्य ग्रह और तारे।

हर शक्ति का एक दिन होता है, लेकिन उन्हें पाने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। योग और तंत्र में, कोई अनुष्ठान नहीं होता, केवल शक्ति की साधना होती है। प्रत्येक दिन की शक्ति और उस शक्ति के स्वरूप को समझना महत्वपूर्ण है।

शक्ति के प्रत्येक रूप का एक नाम है, लेकिन वर्तमान समय में, हम केवल उनके रूपों पर चर्चा करेंगे। नाम केवल विशिष्ट साधनाओं के माध्यम से शरीर में क्षमता उत्पन्न करने के बाद ही लिए जाते हैं। वुनियादी स्तर पर, जब आप अपने गुरु के साथ ध्यान करते हैं, तो आप उनमें कुछ विशेष रूप देख सकते हैं, जैसे सूर्य या यहां तक कि चंद्रमा।

कभी सोचा है कि ये रूप कहां से आते हैं और ये क्या दर्शाते हैं? ऐसे कई साधक हैं जिन्होंने ध्यान में सूर्य के रूप को देखने की सूचना दी है। सूर्य में ऐसा क्या विशेष है? यदि आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखते हैं, मणिपूरक के बारे में जागरूकता रखते हुए और राम मंत्र का जाप करते हैं, तो आप पाएंगे कि शरीर में एक निश्चित चमक आने लगती है और सिर्फ एक महीने के भीतर आप बहुत अलग दिखने लगेंगे (यहाँ सावधानी का एक शब्द, किसी भी योगिक अभ्यास के लिए एक गुरु का होना जरूरी है जो आपकी क्षमता के अनुसार आपका मार्गदर्शन करे)। सूर्य की तरह, चंद्रमा भी एक अत्यंत दिलचस्प

ऊर्जा है। चंद्रमा केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, लेकिन उस प्रकाश के साथ, यह पूर्णिमा की रात इतना ही नहीं, पूर्णिमा की रात को जानवर हिंसक हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्थिर लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं और दुर्घटनाएं और झगड़े बढ़ जाते हैं। अभी मैं केवल मूल पहलुओं पर चर्चा कर रहा हूं, ताकि आपको संकेत मिल सके कि इन रूपों में कुछ अलग है। वह क्या है, यह अनुभव का विषय है और आपको सनातन क्रिया के सही अभ्यास से वह अनुभव प्राप्त होगा।

चंद्रमा की विशेषता यह है कि यह शांत और शांतिपूर्ण दिखता है लेकिन यह सूर्य से भी अधिक अस्थिर है। जब आप गुरु के मार्गदर्शन में चंद्रमा को देखेंगे, तो आप उसके सभी भेदों को उसके रूप में देख पाएंगे क्योंकि आप सूर्य को नहीं देख सकते, जो उस शक्ति को प्रवाहित करता है।

कुछ शक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं और इसलिए कुछ अन्य शक्तियां हैं जिनके माध्यम से आप उनके प्रभाव को देख और महसूस कर सकते हैं, यह आपके लिए एक अनुभव बन जाता है। और जब तक आपको वह अनुभव नहीं हो जाता, तब तक योग आपके लिए व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ भी संभव नहीं है।

अनुभव योग का आधार है। आकाश में और धरती पर हम जो भी चीजें देखते हैं, इतने सारे रंग-बिरंगे फूल हैं, अगर आप गुरु सानिध्य में बिना पलक झपकाए उन्हें देखते हैं, तो शरीर के सभी दोष और असंतुलन गायब हो जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी समस्या है...नियम। अभ्यास में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और रुकावट तब आएगी जब आपके पास उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है या आपके पास कोई गुरु नहीं है।

प्रकृति, हमारे आस-पास जो कुछ भी देखते हैं, उसमें शक्तियों के सभी स्वरूप छिपे हुए हैं और ये सभी शक्तियां बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। अगर कोई इन शक्तियों पर खुद को केंद्रित करता है और उन्हें ठीक से प्राप्त करता है, तो वे उसका अनुसरण करना शुरू कर देती हैं। दिवाली से पहले के नौ दिन विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इन दिनों में विशिष्ट शक्तियों का जमावड़ा होता है। हमारे पूर्वजों ने इन दिनों में ब्रह्मचर्य का व्रत रखने का निर्देश दिया था ताकि शरीर इन शक्तियों को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सके।

आप की बात

सदियों पुरानी परम्परा

कार्तिक मास ऐसे तो पर्व त्योहार वाला महीना है लेकिन सबसे खास दिन कार्तिक पूर्णिमा है इस दिन का इंतजार बुढ़, जवान,लाड़का,सियान सबको रहता है क्योंकि इस दिन लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को मेला के लिए विख्यात है जिसमें हाथी, घोड़ा, बैल, गाय,ऊंट, कुत्ताएवं विदेशी नस्ल के पशु भी मौजूद रहते हैं जोवरा ही आकर्षक केवल प्यारा लगता है जो मिला को खास बनाता है मेले में तरह-तरह की ऊनी स्वेटर, तरह-तरह के व्यंजन, अचार, कपड़ा बाजार, बागवानी बाजार लगते हैं तरह-तरह के झूले एवं प्रदर्शनी मेला कभी आयोजन होता है साथ ही प्रासनविक नुक्कड़ नाटक, मनोरंजन, झांकियां, प्रतियोगिता कभी आयोजन होता है।

- **तारामुनी देवी**, लालगंज, वैशाली

कांग्रेसी ड्रामा

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। शायद विधि के विद्यार्थी या अधिभाषक भी भारत के संविधान को पूरा नहीं पढ़ते होंगे। वे भी आधारित हैं। उपयोगकर्ता भी पूरा संविधान पढ़ा हो। लाल किताब भी प्रतीक ही उन्होंने बताई है। हर चुनाव के प्रचार में वे लाल किताब लेकर ही घूमते रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं और वे (मोदी) उसको खत्म करने वाले। अब उन्हें कौन समझाए कि देश की सरकार संविधान के अनुसार ही चलती चली आ रही है और आगे भी चलेगी। उस भी कोई व्यक्ति या संस्था अथवा सरकार संविधान से इतर काम करती है तो करोड़ों आंखें हैं देश की जो जनहित याचिका लगा कर उनकी आंखें खोल देती हैं और न्यायालय को सही/गलत का निष्कर्ष निकालकर निर्णय देना ही पड़ता है। संविधान बचाओ जैसी बचकानी राजनीति के जरिये कांग्रेस केवल कुर्सी बचाओ अभियान चला रही है। वो अब येन केन प्रकारेण सत्ता पाने की कोशिश कर रही है और बेवजह चलती सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रही है. जबकि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना, समालोचना करना होता है साथ ही सही काम में सहयोग व पटरी से उतरी सरकार को सही निर्णय लेने के लिए व उसे पुनः जनहित में पटरी पर लाना होता है न कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही करते रहना होता है।

- **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

खतरे की घंटी

आखिरकार दिल्ली नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन महापौर की चुनाव में 10-आप के पार्षद की क्रॉस वोटिंग भी सामने आई है जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी नजर आती है। यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि नगर के महापौर का कार्यकाल केवल 5 महीने का रहेगा क्योंकि 7 महीने का मेयर का कार्यकाल राजनीति की भेंट चढ़ गया है. दिल्ली वाले नए मेयर और डिप्टी मेयर से उम्मीद करते हैं कि एमसीडी अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान के लिए बिना देरी के योजनाएं बनाये, रुके हुए कामों को पूरा करें और दिल्ली की मुख्य समस्याएं प्रदूषण, जल निकासी, जल भराव, गंदे पानी का सड़कों पर बहाना एवं नगर निगम के क्षेत्र में सीवर की समस्या और नालियों, टूटी फूटी सड़कें एवं सड़कों का रखरखाव आदि पर फोकस करते हुए काम करना होगा. उम्मीद यह भी है कि राजनीतिक दलों आपसी तालमेल एवं दिल्ली सरकार, एमसीडी और केंद्र सरकार को भी मिलकर दिल्ली को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सभी अपनी सहभागिता जरूरी है।

- **वीरेंद्र कुमार जाटव**, दिल्ली

अवैध प्रवासियों का मुद्दा

अमेरिका 2025 में कुछ नए परिवर्तनों के बीच उभरेगा जब ट्रंप दूसरी पारी में देश की बागडोर को संभालेंगे। चुनावों से पूर्व जनता से किए गए वादों को पूरा करने में कृत संकल्पित ट्रंप अभी से ही उनके नियोजन के प्रयास पर जुट गए हैं। अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप सख्त हैं। उनका मानना है कि अवैध प्रवासी हमारे देश को बाद कर रहे हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर देश से निकाला ही जाएगा।देखा जाए तो ट्रंप की सोच एकदम उचित है और यह न केवल अमेरिका ही बल्कि पूरी दुनिया पर लागू होती है।भारत में भी इसके दुष्प्रभाव लोगों ने देख लिए हैं। अपराधिक गतिविधियों,अवैध धंधे और ड्रग्स की सप्लाई जैसे कृत्यों में लिप्त ऐसे घुसपैठिए युवा पीढ़ी को नशे की लत में बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा घुसपैठिये सरकारी योजनाओं का मुफ्त लाभ भी उठा रहे हैं इससे वास्तविक हकदारों के हित प्रभावित हो रहे हैं।दुनिया में अवैध प्रवासी तभी अपने देशों में स्थानांतरित किये जा सकते हैं जब सरकारें सारे वोट बैंक को नजर अंदाज करके देश हित को प्रमुखता दें जैसे ट्रंप ने चुनावों से पूर्व सीना ठोकर इसकी चुनौती दी थी।

- **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है टाइप 2 मधुमेह के मामलों में, पिछले पांच वर्षों में 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार।

उच्च शिक्षा व्यवस्था

कुलपतियों की नियुक्ति में देरी के दुष्परिणाम

डा. अमरजीत कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एनईपी कोआर्डिनेटर, माधव विवि, सिरोही, राजस्थान

देश में शिक्षा व्यवस्था में सामयिक सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई क्रेडिट फ्रेमवर्क, अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट जैसी कई नई नीतियों को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। चूंकि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कुलपति विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक संचालन का केंद्र बिंदु होते हैं, इसलिए इस कार्य में इनकी महत्ता बढ़ जाती है। परंतु इनकी नियुक्ति के संदर्भ में कई राज्यों में विवाद सामने आए हैं, जिसे उच्च शिक्षा में सुधार की राह में भी एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है

प्रतीकात्मक

भारत में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न नीतियां और योजनाएं लागू की जाती रही हैं। हालांकि इन सुधार प्रयासों के बावजूद कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। पिछले दिनों ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने उच्च शिक्षा विभाग से राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति में तेजी लाने को कहा है। वस्तुतः इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कार्यकाल इस माह के अंत तक समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण है कि कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति लेकर विगत वर्षों में इन संस्थानों में राजनीतिक विवादों का उभार देखा गया है, जिनका खामियाजा छात्रों और शैक्षणिक व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। विशेष रूप से कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित विवाद और राज्यपालों की भूमिका को लेकर उत्पन्न मतभेदों ने उच्च शिक्षा के संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

हाल में तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच छिड़े 'तमिल गान' विवाद ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि ऐसे विवादों की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी। पिछले वर्ष तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित दो विधेयकों ने भारतीय उच्च शिक्षा में राज्यपाल की भूमिका को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य राज्यपाल के पास विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति की शक्ति को राज्य सरकार को स्थानांतरित करना था। तमिलनाडु के इस कदम ने पहले से चल रही बहस को और तेज कर दिया है कि क्या विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होनी चाहिए, या फिर राज्य सरकार द्वारा, जो विश्वविद्यालयों का वास्तविक संचालन देखती है। इन विवादों के मद्देनजर तमिलनाडु के पांच विश्वविद्यालय बिना स्थायी कुलपति के संचालित हो रहे हैं। वैसे तमिलनाडु अकेला राज्य नहीं है जो इस मुद्दे से जूझ रहा है। बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान जैसे कई राज्यों में भी इसी प्रकार के विवाद सामने आए हैं।

छात्रों के हितों की अनदेखी : कुलपति (वीसी) को विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी माना जाता है। उनकी भूमिका विश्वविद्यालय के समग्र प्रशासन, शैक्षणिक कार्यक्रमों की देखरेख और नीतिगत निर्णयों को लागू करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का विकास, नई शैक्षणिक नीतियों का क्रियान्वयन और शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखना संभव हो पाता है। जब विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं होता, तो कई आवश्यक निर्णय लंबित रहते हैं, जिनका सीधा प्रभाव छात्रों की शैक्षणिक यात्रा पर पड़ता है। जैसे कि नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत, दीक्षांत समारोहों का आयोजन और अन्य प्रशासनिक कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते। यह देरी छात्रों के करियर और उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

इसके अतिरिक्त, छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि नेतृत्व की कमी होती है। जब विश्वविद्यालय बिना स्थायी कुलपति के कार्य करते हैं, तो यह संस्थान की रैंकिंग, शोध की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर भी बुरा असर डालता है। कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता भी प्रभावित होती है, जिससे उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आ सकती है। ऐसे में कुलपति नियुक्ति विवाद को जल्द सुलझाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो सके।

कुलपति की भूमिका का महत्व : राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और रामलाल पारीख समिति की रिपोर्टों में विश्वविद्यालयों के विकास और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में कुलपति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। इन समितियों ने विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में कुलपति के योगदान को रेखांकित करते हुए, इसे उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना है। राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और गुणवत्ता लाने के लिए विश्वविद्यालयों को कुशल नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। जबकि कोठारी आयोग ने भी विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार के लिए कुलपति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चल सकें।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुलपति न केवल विश्वविद्यालय का नेतृत्व करते हैं, बल्कि वे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कुलपति की नियुक्ति में देरी या विवाद का विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समय-समय पर आई इन समितियों की रिपोर्टों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि एक कुशल और योग्य कुलपति का नेतृत्व किसी भी विश्वविद्यालय की सफलता और उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है।

संबंधित विवाद का दुष्प्रभाव : उल्लेखनीय है कि कुलपति विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक संचालन का केंद्र बिंदु होते हैं और कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति एवं चयन समितियों के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। इसके अलावा, कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करते हैं और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में छात्रों को उपाधि प्रदान करने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। जब विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं होती या इसमें देरी होती है, तो इन महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। कार्यकारी परिषद, जो विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों को लेने के लिए जिम्मेदार होती है, बिना कुलपति के वह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। इतना ही नहीं, शैक्षणिक परिषद, जो पाठ्यक्रम और शैक्षणिक नीतियों की योजना बनाती है, वह भी नेतृत्व की कमी के कारण निष्क्रिय हो जाती है।

यह स्थिति विश्वविद्यालय की रैंकिंग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी या नैक) की मान्यता प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। नैक रैंकिंग विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता और शोध की क्षमता के आधार पर दी जाती है। जब विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता नहीं होती, तो यह उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है, जिससे उनकी रैंकिंग गिर सकती है। इससे न केवल विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, बल्कि छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता और उनके भविष्य के करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुलपति की नियुक्ति में होने वाली देरी को जल्द सुलझाया जाना चाहिए, ताकि शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा और छात्रों के हितों की सुरक्षा हो सके।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राह में अड़चनें

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को अधिक व्यावहारिक और समग्र शिक्षा प्रदान करना, उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना और उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत कई नई पहलें की गई हैं, जैसे अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट (एबीसी), जो छात्रों को विभिन्न संस्थानों से अर्जित क्रेडिट को जोड़ने और उनका उपयोग एक ही डिग्री के लिए करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, अपार आइडी (आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) और अन्य डिजिटल सुधारों का उद्देश्य शैक्षणिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। हालांकि इन नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विश्वविद्यालयों में स्थायी नेतृत्व और प्रबंधन पर निर्भर करता है। कुलपति की अनुपस्थिति या नियुक्ति में देरी इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा उत्पन्न करती है। जब विश्वविद्यालयों में स्थायी नेतृत्व नहीं होता है, तो प्रशासनिक निर्णयों में देरी होती है, जिससे नीतियों का क्रियान्वयन धीमा पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप छात्र उन शैक्षणिक लाभों से वंचित रह जाते हैं, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सकते थे।

इसके अलावा, नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल रूप से संचालित शैक्षणिक तंत्रों का सही तरीके से लागू होना भी कुलपति के नेतृत्व में ही संभव होता है। विश्वविद्यालयों के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आनलाइन शिक्षा प्रणाली का विस्तार और अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट का सही उपयोग तभी संभव है, जब विश्वविद्यालय में एक स्थायी और कुशल नेतृत्व हो। कुलपति नियुक्ति विवाद को जल्द सुलझाना इसलिए आवश्यक है, ताकि यूजीसी और नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को मिलने वाले लाभों का पूरा लाभ मिल सके। इससे न केवल छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उन्हें एक उज्जवल और प्रतिस्पर्धी भविष्य के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। कुलपति का पद विश्वविद्यालय के प्रशासन और शैक्षणिक नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस पद पर विवाद होने से विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और भविष्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं। यह स्थिति न केवल छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को अनिश्चितता में डाल रही है, बल्कि उच्च शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को भी कमजोर कर रही है। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने के लिए कोई समाधान आवश्यक है, ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए उच्च शिक्षा जगत में उसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

(डा. अमरजीत कुमार)

खरी-खरी

लाइक और कमेंट के वही खाते

रेखा शाह आरबी

'नमस्ते बहन जी।'

'जी, नमस्ते।'

'बहुत दिनों से पोस्ट पर आपके दर्शन नहीं हुए।'

'यही बात तो मैं आपके लिए भी कह सकती हूं, आप भी तो हमारे पोस्ट के तरफ अपना पीठ किए रहती हैं या रास्ता भूल गई हैं।'

'हां, कुछ व्यस्तता है इधर।'

'यहां कौन बेरोजगार है और मुफ्त की बेगारी करने के लिए बैठा है।'

'आप लाइक कमेंट का हिसाब रखती हैं?'

'अरे, आप यह क्या कह रही हैं, कोई भला लाइक कमेंट का भी हिसाब न रखे। मैं तो बहुत सामान्य इंसान हूं, बड़े-बड़े लोग अपने रीच और फालोअर कम होने पर बिलबिला उठते हैं।'

'अच्छा, तो यह भी बता दीजिए आपका हिसाब-किताब क्या है।'

'मेरा हिसाब किताब बहुत सीधा है, मैं लाइक कमेंट अपने पर्सेंट के हिसाब से खर्च करती हूं, न एक इधर न एक उधर।'

'अरे, वह कैसे?'

'देखिए, 50 परसेंट लाइक कमेंट लेखकों के लिए रिजर्व कोटे में रखती हूं, 25 परसेंट उनके लिए जो मेरे पोस्ट पर आते हैं और हम उनके पोस्ट पर जाते हैं उनके लिए, बाकी के 10 परसेंट उनके लिए जिनकी पोस्ट मुझे प्रभावित कर देती है और हंसी चुटकुले वाली पोस्टों के लिए, 10 परसेंट तो यूं ही चले जाते हैं।'

''और पांच का क्या करती हैं?'

'पांच परसेंट उनके लिए मजबूरी में रखना पड़ता है जो मैसेंजर में अपनी पोस्ट लेकर आते हैं और रोने गाने लगते हैं लाइक कमेंट के लिए।'

'बड़ा अच्छा आपका हिसाब किताब है।'

'ये हिसाब-किताब इसी दुनिया के लोगों ने सिखाया है।'

'चलिए छोड़िए, बताइये आप मेरी पोस्ट पर आ रही हैं? कृपया लाइक और एक अच्छा सा कमेंट दीजिए।'

'देखिए इस महीने का रिजर्वेशन कोटा खत्म है, अगले महीने देखते हैं, लेकिन उससे अच्छा एक उपाय है, आप 25 परसेंट वाले कोटे में आ जाइए, आप मेरी पोस्ट पर आइए, मैं आपकी पोस्ट पर आती हूं।'

'आप रहने दीजिए, मैं कहीं और जाती हूं।'

पोस्ट

कनाडा में खालिस्तान समर्थक नारा लगा रहे हैं कि 'कनाडा के असली मालिक हम हैं' और 'श्वेत लोगों को वापस यूरोप और इजरायल चले जाना चाहिए।' आखिर कनाडा ऐसे अराजक लोगों को इसकी गुंजाइश दे भी कैसे रहा है कि वे हमारी विदेश नीति को निर्धारित करें।
डेनियल बोर्डमैन@DanielBordmanOG

दिल्ली के प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब का नाम अब बिरसा मुंडा चौक होगा। यह कांग्रेस कर सकती थी और केजरीवाल भी, पर सराय काले खां चौक का नाम बदला नहीं जा सका। कांग्रेस के दौर में दिल्ली की सबसे बड़ी गंदी झुग्गी बस्ती का नाम अंबेडकर नगर रखा गया। सबसे बड़ी दो सड़कों का नाम महात्मा गांधी और नेहरू के नाम पर तो सबसे प्रमुख चौराहे का नाम राजीव चौक रखा गया।
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

कई लोग आइपीएल को बेवजह कोसते हैं। आइपीएल से ही बीसीसीआइ के पास एक अदृश्य शक्ति आई है। यदि क्रिकेट में पुराना दौर ही कायम रहता तो हमें चैंपियंस ट्राफी के लिए पाकिस्तान जाना ही पड़ता और पाकिस्तान ट्राफी का टूर गुलाम कश्मीर में भी कराता।
राहुल दुबे@Therahul_dubey

जागरण जनमत — कल का परिणाम

भारत में भी सरकारी खर्च घटाने के लिए दक्षता मंत्रालय के गठन की जरूरत है?

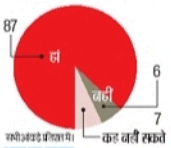

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ट्रंप प्रशासन में विवेक रामास्वामी और तुलसी गबार्ड के शामिल होने से भारतीय हितों की पूर्ति में आसानी होगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

भारतवंशी बन रहे टीम ट्रंप का अंग,
तब तो जमना चाहिए भारत के संग रंग।
भारत के संग रंग लिखे हम नई कहानी,
किस कोने में जाय छिपे अब पाकिस्तानी!
'तुलसी' पूजन बाद चैन की बाजे बंसी,
आपस में स्नेह रखे यदि भारतवंशी!
- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

अपनी उपलब्धियों के बखान में जुटा राजग

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार विधानसभा के चुनाव यदि पांच साल पहले की तिथियों पर हुए तो 2025 में इस समय तक नई सरकार अस्तित्व में रहेगी। वर्ष 2020 में एक अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी। तीन चरणों में मतदान हुए थे। 10 नवंबर को परिणाम घोषित हो गया था। इस हिसाब से राज्य विधानसभा के अगले चुनाव में 11 महीने से भी कम समय बचा है। इधर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें कुछ नए संकेत भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन दिनों के भीतर राज्य की दो यात्रा की। 13 नवंबर को दरभंगा और 15 को जमुई में उनकी सभाएं हुईं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजग के उन घटक दलों के नेता शामिल हुए, जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली हुई है।

इन दोनों सभाओं में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के भाषणों का विश्लेषण करें तो कुछ नई बातें उभर कर सामने आती हैं। बिहार और देश भर में सत्तारूढ़ राजग के नेताओं पर आरोप लगता रहा है कि ये अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय कांग्रेस या गैर भाजपा दलों के शासनकाल की कमियों की गिनती कराते रहते हैं। विपक्ष का यह आरोप गलत भी नहीं है। राजग ने विपक्ष के आरोप का सम्मान किया है या उसके पास गिनाने लायक अपनी उपलब्धियां ही काफी हो गई हैं, दोनों सभाओं में विपक्षी दलों पर न्यूनतम प्रहार किया गया। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में भी राजग के नेताओं का भाषण अपनी उपलब्धियों पर ही केंद्रित रहेगा। यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो होगा ही, विपक्ष के आरोपों की सूची भी थोड़ी कमजोर होगी। क्योंकि दोनों सभाओं में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दो शासन की उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण पेश किया। उनकी कमियां कम और अपनी उपलब्धियां अधिक गिनाईं।

दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के साथ एक ट्रेन को आनलाइन झंडी दिखाते हुए नरेन्द्र मोदी। आइपीआरडी

भाषण शैली में आए इस बदलाव को राजग के जमीनी कार्यकर्ताओं ने भी नोट किया है। उनका उत्साह बढ़ा है। यह विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजग के तमाम प्रयासों के बावजूद विपक्ष के पास जनहित से जुड़े प्रश्न कम नहीं होंगे। विशेषकर रोजगार, नौकरी और महंगाई के प्रश्न ऐसे हैं, जिनसे पूरी आबादी प्रभावित है। फिर भी, केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारें अपनी उपलब्धियों के बल पर यह दावा तो कर ही सकती हैं कि पहले की तुलना में उनके जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं बढ़ी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, उसका लाभ पूरी आबादी को मिल रहा है। केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच पहले की तुलना में बढ़ी हैं। प्रायः सभी योजनाओं का धन डीबीटी के माध्यम से लाभ पाने वाले व्यक्ति के खाते में जा रहा है, इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। देश के दूसरे हिस्से की तरह बिहार में भी यह समस्या थी। केंद्र या राज्य सरकार की ओर से आम लोगों को दी जाने वाली किसी मद की राशि का बड़ा हिस्सा सरकारी-गैर सरकारी बिचौलिए खा जाते थे। यह ऐसा विषय है, जिसकी चर्चा राजग के घटक दलों के नेता-कार्यकर्ता जनता के बीच करते रहे हैं। हां, अपनी उपलब्धियों के बावजूद राजग 1990 से 2005 तक की राज्य सरकार की चर्चा करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि वह शासन काल राजग के पक्ष में जन गोलबंदी का केंद्रीय पक्ष रहा है। इस क्रम में अपराध, भ्रष्टाचार, जंगलराज आदि का चर्चा पहले की तरह होती रहेगी।

पीएम मोदी और सीमए नीतीश भी 15 वर्षों के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की शासन की चर्चा करना नहीं भूल रहे हैं। लेकिन यह केवल संदर्भ के रूप में होता है। इससे पहले यह राजग के भाषण का मुख्य विषय होता था। नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष यह प्रचार करने से कभी नहीं चूकता है कि ये किसी भी समय उधर से इधर (राजग से महागठबंधन) आ जाएंगे। विपक्ष के इस प्रचार का प्रभाव राजग कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है। नीतीश ने इसकी भी काट खोज ली है। अब वे अपनी हरेक सभा में इधर-उधर जाने की घटना को अपनी गलती मानते हैं। इसके लिए स्वयं के बदले अपने कुछ विश्वस्त सहयोगियों को जवाबदेह ठहराते हैं। पीएम की सभा से लेकर राजग की अपने आवास पर आयोजित बैठक और जदयू की अंदरूनी बैठकों में भी नीतीश इस संकल्प को अनिवार्य रूप से दोहराते हैं कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजग को छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। इसका प्रभाव केंद्र से लेकर राज्य कैबिनेट में शामिल भाजपा के मंत्रियों और आम कार्यकर्ताओं पर भी देखा जा रहा है। नीतीश के इस संकल्प को नीचे तक ले जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर राजग कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जा रही है।

मंथन

भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य की चिंता

डा. नीलम महेंद्र
सामाजिक मामलों की जानकार

भारत एक युवा देश है। ऐसे में बच्चों एवं युवाओं में बढ़ता स्वास्थ्य का जोखिम एक नई चिंता पैदा कर रहा है, जिसका समय रहते समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है

कभी वयस्कों में देखी जाने वाली बीमारी मधुमेह अब युवाओं और बच्चों तक को बड़ी संख्या में अपनी चपेट में ले चुकी है। युवाओं में मधुमेह रोग जिस प्रकार अपने पैर पसार रहा है, उसके दूरगामी दुष्प्रभाव केवल इनके स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर भी निश्चित तौर पर पड़ेंगे। सबसे निराशाजनक पहलू यह है कि देश की युवा पीढ़ी में मधुमेह के बढ़ते मामले आधुनिक जीवनशैली से जुड़े हैं। क्योंकि एक तरफ वर्तमान जीवनशैली के चलते हमारी शारीरिक गतिविधियां सीमित हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटाइजेशन के कारण स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच शारीरिक खेल और बाहरी गतिविधियां बच्चों के जीवन में कहीं पीछे छूट गई हैं। जैसे-जैसे तकनीक अधिक सुलभ होती जा रही है, बच्चे स्क्रीन के सामने अधिक समय व्यतीत रहे हैं और दौड़ने या खेल में कम समय बिता रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हालिया रिपोर्ट इस गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले पांच वर्षों में 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में टाइप 2 मधुमेह की घटनाओं में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि यह वृद्धि केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में यह विचलित करने वाला तथ्य भी सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में बढ़ते मोटापे के कारण उनमें टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा तीन गुना तक बढ़ गया है।

जीवनशैली से जुड़ी बीमारी : विभिन्न शोध अध्ययनों के माध्यम से आज यह बात सिद्ध हो चुकी है कि टाइप 2 मधुमेह एक जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है। यह तब होती है जब हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या जब अग्न्याशय सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है। अधिकांश तौर पर यह बीमारी वयस्कों से जुड़ी होती है, लेकिन गतिहीन जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर आहार और मोटापे के कारण आज यह बच्चों में भी तेजी से अपने पैर पसार रही है। बच्चों में मधुमेह का बढ़ना चिंताजनक है, क्योंकि इस बीमारी के साथ होने वाली दीर्घकालिक जटिलताओं के कारण हृदय संबंधी समस्याएं, गुर्दे की बीमारी, तंत्रिका क्षति और यहां तक कि दृष्टि हानि भी हो सकती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, पिछले दशक में टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित बच्चों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में भारत में लगभग 20 लाख बच्चों के इस बीमारी से पीड़ित होने की आशंका जताई गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में यह संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। वस्तुतः शारीरिक गतिहीन जीवनशैली के अतिरिक्त आहार की हमारी बदलती आदतें भी इन परिस्थितियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पारंपरिक, घर का बना खाना, जो कभी भारतीय परिवारों की पहचान था, आज उसकी जगह फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स ने ले ली है। एक संबंधित रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है।

डिजिटाइजेशन के कारण बच्चों एवं युवाओं की बाहरी गतिविधियां कम होती जा रही हैं। प्रतीकात्मक

शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन : वैसे इस संबंध में एक अच्छी खबर यह है कि मधुमेह, खास तौर पर टाइप 2 मधुमेह को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देकर और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके हम वर्तमान आंकड़ों को पलट सकते हैं। अनेक शोध अध्ययनों में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जिन लोगों ने स्वस्थ आहार-विहार और शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी जीवनशैली में बदलाव किया, वे काफी हद तक मधुमेह से लड़कर जीते भी हैं।

आज जब हम इस संकट का सामना कर रहे हैं तो एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, इस देश के एक जागरूक नागरिक के रूप में, माता-पिता के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि इस देश के हर बच्चे को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। आइए सुनिश्चित करें कि वे मैदानों में खेलें, दोस्तों के साथ तितलियों के पीछे दौड़ें, अपने बचपन को स्क्रीन के आगे नहीं, बल्कि बाग बगीचों और खुले मैदानों में जिएं, ताकि मधुमेह जैसी बीमारियों की आशंकाओं से मुक्त होकर बड़े होने का सपना देख सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।

****

दैनिक जागरण

आंतरिक अंधकार को दूर किए बिना बाहरी प्रकाश व्यर्थ है

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

राहुल वर्मा

छोटी पार्टियां तो निजी जागीरों की तरह चलाई ही जा रही हैं, बड़े दलों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं

अशोक त्रिपाठी

समकालीन भारतीय राजनीति में दलबदल एक ऐसी दलदल है जिसमें लगभग हर कोई राजनीतिक दल धंसा हुआ है। ज्यादा दूर न जाएं तो चले अप्रैल से जून तक चले लोकसभा के चुनाव तो या बीते दिनों हुए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव से लेकर इन दिनों चुनावी प्रक्रिया का सामना कर रहे महाराष्ट्र-झारखंड का उदाहरण लें तो कुछ नेताओं को लेकर आपको चुंबिश हो सकती है कि वे इन दिनों किस पार्टी के सबब जुटे हैं। दौनों राज्यों में सभी दल असंतुष्ट और बागी प्रत्याशियों से जुझ रहे हैं। अस्सल में नेताओं और दलों ने दलबदल को इतना सामान्य बना दिया है कि मानो यह कोई मुद्दा ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं। पहले नैतिकता का तकाजा हो या फिर आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो दलबदल की यह परिपाटी राजनीतिक तंत्र में भारीसे और खिरवसनैयता का सबाल निश्चित रूप से उठाती है। हमारी व्यवस्था में यह सिलसिला कहीं काय्म है? वस्तुतः उसमें चुनाव सुधारों का अभाव दिखेगा। हमारे कुछ नेताओं की निहित स्वार्थ से प्रेरित यह मान्सिकता भी इसके मूल में है जो किसी भी स्थिति में सत्ता में भागीदार न सही तो कम से कम उसके करीब जरूर रहना चाहती है।

दलबदल अमूमन दो तरह से होता है। एक तो चुनाव से पहले और दूसरा चुनाव के बाद। स्वाभाविक है कि चुनाव में टिकट से वंचित रह जाने की स्थिति में लोग पाला बदल लेते हैं। हालांकि इसके उतने खतरे नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले ही मतदाताओं के समक्ष स्थिति स्पष्ट रहती है कि कौन किसके पाले में है। दौनों स्थितियों में चुनाव बाद होने वाला दलबदल कहीं अधिक गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि उसमें मतदाताओं के साथ छल होने का जोखिम अधिक रहता है। शायद यही कारण रहा कि चुनाव बाद होने वाले दलबदल पर अंकुश के लिए वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार ने दलबदल निरोधक कानून बनाया, जिसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने और सशक्त बनाने का काम किया। इससे चुनाव बाद दलबदल की समस्या का कुछ हद तक समाधान अवश्य हुआ, लेकिन उसका पूरी तरह निराकरण नहीं हो पाया। नेताओं ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। चूंकि दलबदल के लिए एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है तो उसका बंटीबस्त करने के बाद अब यह कहीं अधिक संस्थागत रूप से होने लगा है। यहां तक कि निर्वाचन के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर बहुमत के आंकड़े को ही विरूपित कर दिया जाता है। उसके बाद उपचुनाव से चुनावी प्रक्रिया और भी बोझिल होने लगी है। वहीं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले गठबंधन के दल भी जब सत्ता की खातिर अपने राह अलग कर लेते हैं तो वह भी जनमत और जनादेश के साथ एक प्रकार का छल होता है।

दलबदल की समस्या समय के साथ और विकराल हुई है तो उसके सबसे अधिक दोषी हमारे राजनीतिक दल हैं। छोटी पार्टियां तो निजी जागीरों की तरह चलाई ही जा रही हैं, मगर बड़े दलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। बड़ी पार्टियों का नेतृत्व भी हद से अधिक केंद्रीकृत हो चला है। आंतरिक लोकतंत्र भी आदर्श अवस्था में नहीं है। प्रत्याशी चयन की सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है। टिकट वितरण में पार्टी कार्यकर्ता की कर्मठता एवं समर्पण सरीखे पहलू अक्सर गौण हो जाते हैं। उसमें केवल जिताऊ कोण पर ही पूरा जोर दिया जाता है। ऐसे में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किनारे करके धनबल, बाहुबल और जातीय-धार्मिक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाने लगी है। खासतौर से चुनाव जितने खर्चीले होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए धनबल की महत्ता बढ़ती जा रही है। ऐसे में धनाढ्य प्रत्याशियों की तरजीह मिलने लगी है। ऐसे दावेदारों को अगर कुछ कारणों से अपने दल से टिकट नहीं मिलता तो प्रतिद्वंद्वी दल उन्हें हाथोंहाथ अपना लेता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि दल की सदस्यता लेने के पांच मिनट में ही उक्त व्यक्ति को पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। आधे घंटे पहले तक किसी के पक्ष में रैली कर रहा नेता एकाएक दूसरे दल के मंच पर पहुंचकर उसकी पैरवी करने लगता है। यह भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की विडंबनाओं की ही उजागर करता है।

दलबदल पर विराम लगाने के लिए कोई कानूनी पहल अनिवार्य रूप से कारगर नहीं हो सकती। दलबदल निरोधक कानून के दुष्परिणामों को ही देख लीजिए। उसके लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत अधिकार बहुत सीमित हो गए हैं कि कई मुद्दों पर वे अपना पक्ष भी नहीं रख सकते। कई राजनीतिक प्रेक्षक इस स्थिति की व्याख्या ऐसे करते हैं कि दलबदल निरोधक कानून लागू होने के बाद जनप्रतिनिधि एक प्रकार से राजनीतिक दलों के 'बंधुआ' बनकर रह गए हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि जनता स्वयं इस मामले में जागरूक होकर राजनीतिक दलों को जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने के लिए बाध्य करे। सभी दल हमारी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी दोषपूर्ण कमियों को दुरुस्त करने का काम करें और उसे से लंबित राजनीतिक एवं चुनाव सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाएं।

अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के देशों से इस मामले में कोई सीख ली जा सकती है। हमारे दल पश्चिम की सुगठित एवं राजनीतिक व्यवस्था के सकारात्मक बिंदुओं को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से लेकर चुनावी फीडिंग और राजनीतिक समायोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पश्चिम के परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में दलबदल जैसी कोई समस्या नहीं, लेकिन वह इतनी विकराल नहीं है। वहां नेताओं से लेकर राजनीतिक दल अपने वैचारिक आग्रह को लेकर सख्त रुख अपनाते हैं और विचारधारा की राजनीति ऐसी नहीं कि उसे एकाएक केंचुली की तरह बदल दिया जाए। उसके भारत में विचारधारा के पालकी ढोने का दावा करने वाले नेता भी इस मामले में उसे कपड़ों की तरह बदल लेने से परहेज नहीं करते। ऐसे में यदि विचारधारा, आंतरिक लोकतंत्र और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया जाए तो दलबदल की समस्या पर बड़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

पारदर्शिता को प्रोत्साहन

मोदी सरकार की अपने घर का सपना पूरा करने वाली पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में जो विभिन्न सुधार किए गए, उनमें सबसे उल्लेखनीय यह है कि अब आवेदक यह भी जान सकेंगे कि उनके आवेदन की क्या स्थिति है। इससे उन्हें केवल यही पता नहीं चलेगा कि उनके अपने घर का सपना कब तक पूरा होगा, बल्कि कोई अड़चन आने पर वे इससे भी अवगत हो सकेंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके चलते सरकार को भी पीएम आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले घरों को समय पर पूरा कराने में आसानी होगी। पीएम आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के पहले चरण में 1.18 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दी गई थी। इनमें से अधिकांश बन चुके हैं। इस योजना के दूसरे चरण में एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दस लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें से 2.3 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी भी शामिल है। इतनी बड़ी राशि का समय पर सही उपयोग हो, इसके लिए हरसंभव उपाय किए जाने चाहिए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी लोगों को एक अदद छत कब नसीब हो पाएगी, जिनके पास अपना घर नहीं है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पीएम आवास योजना करोड़ों लोगों की अभिलाषा को पूरा करने में सहायक बन रही है।

आवास विहीन लोग जब अपना घर हासिल करते हैं तो वे नागरिक सुविधाओं से लैस होकर बेहतर जीवन जीने के साथ स्वयं को कहीं अधिक सक्षम भी महसूस करते हैं। वे अपनी आय बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं और इस तरह राष्ट्र के आर्थिक उत्थान में सहायक होते हैं। केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें, उन्हें ऐसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। यह ठीक नहीं कि जब लोगों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से अधिकाधिक सक्षम बनाने वाली योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, तब लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने की होड़ मची है। अनुत्पादक अथवा सुपरफ्लोरो को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की होड़ को खत्म करने की जरूरत है। सरकारी धन का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने में नहीं होने दिया जाना चाहिए। यह सही समय है कि प्रत्येक सरकारी योजना में लोगों को वैसी ही सुविधा दी जाए, जैसी पीएम आवास योजना के आवेदकों को दी जा रही है। इससे न केवल योजनाओं के अमल में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करने में मदद भी मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकारी कामकाज में अभी भी पारदर्शिता का अभाव है। कम से कम यह तो हर सरकारी विभाग में होना चाहिए कि लोगों को यह पता चले कि उनके आवेदन की क्या स्थिति है या फिर उन्हीनें जो शिकायत की है, उसका समाधान कहां और क्यों अटका है?

चिंताजनक स्थिति

उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हर साल दुर्घटनाओं का शिकार होकर हजारों लोगों की असमय मौत हो जाती है, फिर भी सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों का उदासीन रहना अत्यंत खेदजनक है। यह अत्यंत ही चिंताजनक स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे 14 जिले हैं, जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक तक नहीं कर रहे। निश्चित रूप से यह अधिकारियों की शिथिलता है जो लोगों की जिंदगी को अपनी प्राथमिकता में नहीं शामिल कर रहे हैं। ऐसा तब है, जबकि इसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनी समिति कर रही है। जिलों में जनवरी से अक्टूबर तक दस बैठकों तो जानी चाहिए थी जिनमें दुर्घटनाओं के कारण और उनको रोकथाम के उपायों पर विचार होता, लेकिन बलरामपुर में केवल दो बैठकें की गईं। इस स्थिति के लिए बरेच्छ अधिकारी भी उत्तरदायी हैं। देश में सड़कों पर सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में यहां दुर्घटनाओं में 23,652 लोगों की मौत हुई थी। अब जबकि मौसम करवट ले रहा है और कोहरे ने सड़कों को ढकना शुरू कर दिया है। ऐसे में गत वर्ष की वे घटनाएं स्मृति पटल पर उभरना स्वाभाविक है, जिन्होंने एक झटके में दर्जनों जिंदगियों को छीन लिया था। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसमें यह बात निहित होती है कि कहीं न कहीं ब्लाइन्ड स्पाट की लापरवाही है अथवा रोड इंजीनियरिंग की कोई कमी है। ऐसी ही स्थितियों को ध्यान में रखकर सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक की जाती है। जहां भी दुर्घटना में तीन से अधिक लोगों की जान जाती है वहां समिति को निरीक्षण करना था, कारण पर मंथन करना था। मंशा थी कि उसी के अनुरूप लोगों को जागरूक किया जाए। दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में अनेक ऐसे जिले हैं जहां सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ही नहीं हो रही।

मेधावी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण योजना

प्रणय कुमार

समाज-राष्ट्र की आवश्यकताके अनुकूल पाठ्यक्रमों में बदलाव की मांग पूरी होनी भी आवश्यक है

छात्रों के लिए एक और उपयोगी योजना। फाइल

शिक्षा विकास की गति एवं दिशा प्रदान करती है। शिक्षा के अभाव में समाज एवं राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता। शिक्षा ही जनतंत्र की मजबूती प्रदान करती है तथा जनतांत्रिक प्रक्रिया में आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। इसे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते दिनों प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को स्वीकृति प्रदान की, ताकि मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हरसंभव सहायता की जा सके और किसी प्रकार की आर्थिक बाधा उनकी प्रगति में अवरोधक न बनने पाए। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की संस्तुति पर की गई एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सुझाव दिय गय था कि निजी और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना से देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले 860 उच्च शिक्षण संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग सरल होगा। इसमें उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अंतर्गत बहुत मामूली ब्याज दर पर विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराय जाएगा। इस ऋण के लिए किसी गारंटी या जमानत की कोई शर्त नहीं रखी गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय आठ लाख रुपये या उससे कम है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर तीन प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान की गई है।

आंकड़े बताते हैं कि ऋण लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या अभी लगभग तीन लाख है। अनुमान है कि इस योजना के बाद शिक्षा-ऋण लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। यह योजना निर्धन, वंचित, निम्न एवं मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उनकी रुचि के पाठ्यक्रमों एवं संस्थानों में प्रवेश के द्वार खोलेगी तथा उन्हें कैरियर की मुख्यधारा में भी सम्मिलित करेगी।

शिक्षक के क्षेत्र में सुधारों एवं अवसरों को गति प्रदान करने तथा कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में मोदी सरकार निरंतर सक्रिय है। बीते एक दशक में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के संस्थान स्थापित हुए हैं। यदि बदलाव की इन तस्वीरों को आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो इनमें सात आइआइटी, 16 आइआइआइटी, सत आइआइएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। देश में पहले राष्ट्रीय महत्व के लगभग 75 संस्थान थे, जो अब दोगुने से भी अधिक बढ़कर 165 हो चुके हैं। पहले देश में 316 सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे, जो अब बढ़कर 480 हो गए हैं। देश में तकनीकी विश्वविद्यालयों की संख्या जहां पहले 90 थी, वह अब बढ़कर 188 हो चुकी है। पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 2014 में 30,000 थी, जो 2024 में बढ़कर 70,000 हो चुकी है। 70 वर्षों में देश में 387 मेडिकल कालेज बने थे, लेकिन पिछले दस वर्षों में ये बढ़कर 706 हो गए हैं। एमबीबीएस सीटों की संख्या पचास हजार से बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई है। पहले देश में 38,000 कालेज थे, जो अब बढ़कर 53,000 हो चुके हैं। ऐसे तमाम आंकड़े, पहल एवं प्रयास उच्च शिक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता, प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता को दर्शाते हैं, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे अन्य अनेक क्षेत्र हैं, जहां और अधिक प्रयास किए जाने तथा कार्य में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। सबसे अधिक आवश्यकता शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की है।

यह सर्वविदित है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में परिवर्तन की प्रतीक्षा दशकों से की जा रही है। जनमानस में इसे लेकर कोई दुविधा या आपत्ति नहीं है, परंतु पाठ्यक्रम परिवर्तन की दिशा में शिक्षा मंत्रालय एवं सरकार की चाल सम्भाव्य से बहुत अधिक धीमी एवं सुस्त नजर आती है। अभी तक केवल पहली, दूसरी, तीसरी एवं छठी कक्षा की पाठ्यपुस्तकें ही प्रकाशित हो पाई हैं। उल्लेखनीय है कि 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब उसने जनभावनाओं एवं पाठ्य-सामग्री आदि पर व्यापक विचार-विमर्श किए बिना ही 2006 यानी केवल दो वर्षों में सभी विषयों एवं सभी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें बदल दी थीं, परंतु वर्तमान सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, जबकि उसके पास पाठ्यक्रम परिवर्तन को लेकर नई शिक्षा नीति के समग्र एवं व्यापक दिशानिर्देश एवं स्पष्ट संस्तुतियां भी हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सबसे तीस एवं निर्णायक कदम बिना कोई देरी किए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता के अनुकूल वंछित परिवर्तन करना ही होगा। इसके लिए तकनीकी, व्यावसायिक, कौशल-आधारित, मूल्यपरक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

पिछले एक दशक में शिक्षा के भारतीयकरण के गंभीर प्रयास और तीव्र हुए हैं। शैक्षिक जगत में भारतीय ज्ञान-परंपरा जैसे विषय चिंतन एवं चर्चा के केंद्रबिंदु बने हैं, परंतु नई शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर दी भारतीय एवं एक विदेशी तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक भारतीय एवं एक विदेशी भाषा पढ़ाए जाने की जो संस्तुति की गई थी, अभी तक उस दिशा में न तो विभिन्न बोर्डों की ओर से ही कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है, न ही मंत्रालय की ओर से ही कोई ठोस एवं निर्णायक पहल की गई है। वास्तव में मातृभाषा अथवा भारतीय भाषाओं को विद्यालयी स्तर पर प्रश्रय एवं प्रोत्साहन दिए बिना शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास अधूरा ही माना जाएगा।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता-असफलता

आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक भय में जी रहा है। उसके मन में उथल-पुथल चलती रहती है कि ऐसा होगा तो क्या? ऐसा न हुआ तो क्या? ऐसे प्रश्नों के जाल में हम स्वयं को उलझाते रहते हैं। हम असफलता से डरते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो यह दावा कर सके कि उसने कभी भी कोई असफलता नहीं देखी। बचपन में जब शिशु अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल परिश्रम करके चलने की कोशिश करता है तब क्या होता है? क्य वह पहले प्रयास में ही चलने में सफल हो जाता है? न जाने कितनें बार बालक रेते-रेते गिरता है, उसके बाक्जूद वह फिर से चलने की ठानकर उठ खड़ा होता है।

जब बचपन में असफल होते होते हुए भी हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना सीख लेते हैं तो फिर वयस्क होने के बाद ऐसी सीख को क्यों विस्मृत कर देते हैं? जबकि हमारे पास प्रेरणा के लिए कई प्रेरक व्यक्तित्वों के उदाहरण होते हैं, जिनकी असफलता के हर कदम की सफलता की सीढ़ी बनकर भव्य सफलता हासिल की और प्रेरणास्रोत बन गए। उनसेंने विफलता को व्यक्तिगत रूप से न लेते हुए एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा और अपनी रणनीति का पुनः मूल्यांकन कर इच्छित परिणाम को हासिल किया। असफलता की स्थिति में स्वयं को हेय समझकर हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। आप जितना परिश्रम करते जाते हैं, मुश्किलें उतनी ही आपके समक्ष झुकती जाती हैं। वास्तविक रूप से असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि हमने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। तो चलिए आज से प्रत्येक विफलता के साथ कुछ सीखें और उससे प्राप्त बहुमूल्य अनुभवों से अपने जीवन को समृद्ध करें, क्योंकि जो अपने राह बनाता है, वही सफलता के शिखर पर चढ़ता है। इसके विपरीत जो दूसरों की राह ताकता है तो सफलता भी उसका मुंह दूर से ही ताकती रहती है।

राजयोगी ब्रह्माकुमार निकुंज जी

यूरेनियन प्रणाली में जीवन संभव!

प्रदीप

यूरेनस एवं उसके चंद्रमाओं में महासागर हो सकते हैं, जहां जीवन की संभावना हो सकती है

सौरमंडल के बेहद ठंडे और दूरस्थ ग्रहों में से एक यूरेनस (अरुण) के बारे में काफी हद तक हमारी जानकारी सम्भाव 1986 में नासा के वोयेजर अंतरिक्ष यान वायजर-2 के पांच दिवसीय उड़ान (फ्लाईबाई) पर आधारित है। इस उड़ान के कारण विज्ञानियों में यह आम धारणा बन गई कि यूरेनियन प्रणाली (यूरेनस और उसके चंद्रमा) एक अंधकारमय, उजाड़ और निर्जीव दुनिया है। लेकिन अब इस उड़ान के 38 सल बाद वायजर-2 से मिले डाटा का विश्लेषण करने वाले एक नए अध्ययन से पता चला है कि यान ने अस्वाभाव्य परिस्थितियों के बीच उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान एक रात्तिशाली सौर तूफान आया था। यूरेनस एक असम्भाव्य प्रकार के अंतरिक्ष मौसम से प्रभावित हुआ था, जिसने इसके चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, जिससे उसका चुंबकीय क्षेत्र नाटकीय रूप से संकुचित हो गय था। फलाईबाई से ठीक पहले गतिशील सौर वायु दबाव 20 गुना बढ़ गया था। इस कारण यूरेनस और विशेष रूप से इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में वायजर-2 ने भ्रामक अवलोकन किए। इससे यह धारणा स्थापित हुई कि यूरेनस और उसके चंद्रमा बंजर, निर्जीव और सुनसान हैं। यह समझा जा रहा है कि यूरेनस और उसके चंद्रमाओं में छिपे महासागर हो सकते हैं, जहां जीवन के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

'नेचर एस्ट्रोनामी' जर्नल में प्रकाशित हालिया शोधपत्र के मुताबिक अब तक हम 40 वर्षों से यूरेनस की गलत नजरिए से देख रहे थे। वायजर-2 से मिले नए परिणाम यह संकेत देते हैं कि यूरेनियन प्रणाली कहीं अधिक दिलचस्प हो सकती है, जहां जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां मौजूद हो सकती हैं। यूरेनस के प्रमुख चंद्रमाओं जैसे टाइटेनिया, ओबेरान, मिरांडा, एरियल और अंब्रियल विज्ञानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। इन उपग्रहों की सतह पर पानी, जमी हुई गैसें और कुछ जैविक अणुओं के संकेत पाए गए हैं। टाइटेनिया और ओबेरान जैसे बड़े उपग्रहों में भूमिगत महासागरों की संभावना जताई गई है, जो पृथ्वी के समुद्रों के समान ही हो सकते हैं। ये महासागर जीवन के लिए अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर हाइड्रोथर्मल वेंट्स (गर्म पानी के स्रोत) हैं, जो गर्मी और आक्सयक रसायनों का स्रोत बन सकती है।

यूरेनस के बातावरण और उसके चंद्रमाओं के बारे में अधिक विस्तृत और स्पष्ट जानकारी के लिए नए मिशनों की आवश्यकता है। हालिया अध्ययन एक नए दृष्टिकोण को उजागर करता है, जो यूरेनस और उसके चंद्रमाओं की संभावनाओं को फिर से जांचने का आह्वान करता है। माना जा रहा है कि 2045 तक 'यूरेनस आर्बिटर एंड प्रोब' मिशन इस अद्भुत प्रणाली में जीवन के संकेतों की खोज करेगा, जो अंतरिक्ष-अन्वेषण की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

बुलडोजर कार्रवाई पर बहस

'बुलडोजर कार्रवाई' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में इस मुद्दे की विवेचना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपितों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई के संदर्भ में निर्णय सुनाय और कुछ दिशानिर्देश भी दिए। बुलडोजर कार्रवाई के अपने गुण-दोष हो सकते हैं, किसी शीर्ष अदालत को इस पर भी विचार करन चाहिए कि आखिर जनता के बीच ऐसे कार्रवाई को स्वीकार्यता या कुछ हद तक समर्थन क्यों बढ़ा है? इसका उत्तर खोजे जाए तो इसकी पृष्ठभूमि में अदालती न्याय में होने वाला अतिशय विलंब भी एक कारण के रूप में सामने आएगा। अगर अदालतें समय से कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएं तो लोग बुलडोजर कार्रवाई को कभी समर्थन नहीं देंगे। जनता के बीच आम धारणा यही है कि कुछ प्रभावी वकीलों से जुड़े मामलों पर तो तत्काल सुनवाई हो जाती है, लेकिन अन्य मामलों में ऐसा नहीं हो पाता। यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम बुलडोजर कार्रवाई एक निश्चित प्रक्रिया के अभाव में आगे बढ़ीं, लेकिन उनमें से तमाम लोगों से जुड़े मामले वर्षों से अदालतों में लंबित थे। ऐसे में उनके विरुद्ध हुई कार्रवाई पर कोई जनाक्रोश देखने को नहीं मिला। उलटे एक प्रकार का संतुष्टि भाव दिखा कि चलो किसी प्रकार कोई कार्रवाई तो हो रही है। हमारे देश में अवैध निर्माणों का सिलसिला अनियंत्रित है। इसे इससे ही समझा जा सकता है कि वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, रेल पथों आदि पर बने अवैध निर्माण हटाए जाएं। रेल मंत्रालय को ही इसके लिए 740 स्थानों की पहचान करनी थी। इसके बावजूद अभी तक केवल 154 स्थानों पर ही अतिक्रमण हटाए जा सके हैं। इसी तरह अवैध निर्माण हटाने के मामले में भी स्थिति है। ऐसे में यदि अदालतें अपने स्तर पर ही इस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय करें तो बेहतर होगा।

पवन यादव, भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली

मेलबाक्स

निर्णय को 15 साल से अधिक हो गए, लेकिन इस मामले में कितनी प्रगति हुई यह किसी से छिपा नहीं। स्मरण रहे कि जब लोगों में कानून के भय का भाव समाप्त होने लगे तो कानून को भी राह बदलनी पड़ती है। 'बुलडोजर' ऐसा ही एक पड़ाव है।

स्वोतस शुक्ल, लखनऊ

प्रदूषण का मानव सभ्यता पर दुष्प्रभाव

बीते कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय है। लेकिन अब यह बात आम लगने लगी है। लोग सोचते हैं कि प्रदूषण हो तो है, क्या हो जाएगा? खतरनाक यह है कि यदि आपके इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक है तो आप रोज 25 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। संविधान के जीवन जीने के अधिकार के तहत हम सबको शुद्ध हवा का अधिकार भी देता है, जीवन जीने के अधिकार का मतलब केवल जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करना नहीं है, इसके अंतर्गत एक अच्छा गुणवत्ता वाला जीवन जीना भी है। सरकार और उसकी नीतियां इसमें विफल होती दिखती हैं। अगर राजनीतिक आकाओं की बात की जाए तो हमें एक अलग ही आयोग प्रत्यरोप का सिलसिला देखने को मिलता है। हमें बातें नहीं बदलाव चाहिए, झूठे वादे नहीं, जो संविधान में अधिकार मिला है, उसे पूरा कर सके ऐसी नीतियों का परिणाम चाहिए।

पवन यादव, भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली

आखिर हिंदू से ही शत्रुता क्यों...

'भारत से आस लगाए बांग्लादेशी हिंदू' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में कृष्णकांत चौबे ने बांग्लादेश में निंदीष हिंदुओं पर हुए हमलों का मार्मिक वर्णन किया है। प्रश्न यह भी उठता है कि अखिर संपूर्ण विश्व में अधिकांशतः पीड़ित हिंदू ही क्यों हैं? हिंदुओं से ही तुरमनी क्यों? जबकि हिंदू जहां भी रहते हैं, उस देश के संविधान, मान्यताओं एवं संस्कृति के प्रति हमेशा आदर की भावना रखते हैं, उसके प्रति निष्ठावान होते हैं। बांग्लादेश में इसके धार्मिक कारण तथा वहां बहुसंख्यकों की कट्टरपंथी मानसिकता तो स्पष्ट नजर आती ही है। चूंकि हिंदू संस्कृति का आधार राष्ट्र भारत है, अतः भारत के प्रति दुराग्रह भी इसका कारण है। इसके पीछे का उद्देश्य यदि भारत और भारत की सरकार को अस्थिर करन है, तो भारत की जनता को भी सचवान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भारत की राजनीति में भी ऐसे अनेक लोग नजर आते हैं जो परोक्ष रूप से विदेशी हितों के साथ खड़े हैं।

विपिन गैयल, हापुड़, उत्तर प्रदेश

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खतकमाण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्करण- रा. पूर्वांचल गुप, पूर्व प्रधान संपादक- रा. नरेन्द्र मोहन, पंच एग्जीक्यूटिव पब्लिशर- मोहित मोहन गुप्त, प्रकाशक संपादक- मंजय गुप्त, जगरण प्रकाशन लि. के लिए, वीनोद बीथाल द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उसी के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : जनरिपोर्ट कार्यालय : 011-43166300, वेबसाइट कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवादों पर नोएडा के अतिरिक्त दिल्ली न्यायालय का अधिकारक्षेत्र होगा। हमारे लेख पृष्ठ ₹-2 अतिरिक्त।

****